पेज 03 में...
हनीट्रैप-2 का राष्ट्रीय ब्लास्ट

साप्ताहिक
शहर सत्ता
PRGI NO. CTHIN/25/A2378
सोमवार, 25 मई से 31 मई 2026
हम दिखाएंगे आईना...

पेज 12 में...
बस्तर के जंगलों में सेवा समर्पण की तीन मिसालें

वर्ष : 02 अंक : 12 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 09 सौम्यता के प्रतीक विष्णु देव साय का सुशासन तिहार

उज्जर, नवा अंजोर

बस्तर का विज़न डाक्यूमेंट पीएम मोदी, एचएम शाह, सीएम साय का ख्वाब

विकास यादव/प्रदीप चंद्रवंशी

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के लिए एक नए दौर की शुरुआत का संकेत देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर "बस्तर 2.0" का विजन डॉक्यूमेंट उन्हें सौंपा। इस दस्तावेज में बस्तर के लिए समग्र विकास की 360 डिग्री योजना प्रस्तुत की गई है, जिसमें पर्यटन, बुनियादी ढांचा, स्टार्टअप, कृषि, शिक्षा और नवाचार को केंद्र में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर आने का आमंत्रण भी दिया है। प्रस्तावित दौरे के दौरान क्षेत्र में कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किए जाने की योजना है। माना जा रहा है कि यह दौरा बस्तर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले वर्षों में सुरक्षा बलों और सरकार के संयुक्त प्रयासों से बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद की जड़ें काफी कमजोर हुई हैं। अब क्षेत्र में शांति और विश्वास का माहौल बन रहा है। ऐसे समय में विकास को नई रफ्तार देकर बस्तर को देश के अग्रणी क्षेत्रों में शामिल करने का अवसर सामने है।

मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत ब्लूप्रिंट "सैचुरेशन, कनेक्ट, फैसिलिटेट, एम्पावर और एंगेज" की रणनीति पर आधारित है। इसका उद्देश्य है कि बस्तर के दूरस्थ वनांचल में भी विकास की सुविधाएं समान रूप से पहुंचें।

विकास की प्रमुख योजनाएं और रणनीतियां

बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी

इसके तहत सबसे पहले बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। बस्तर के अनेक गांव आज भी घने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों के बीच बसे हुए हैं। इसे बदलने के लिए सड़कों और पुलों का व्यापक नेटवर्क तैयार करने की योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधूरे कार्यों को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 228 नई सड़कों और 267 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

कनेक्टिविटी व ऊर्जा: प्रमुख प्रस्तावों में रावघाट-जगदलपुर रेललाइन को तेजी से पूरा करना, जगदलपुर एयरपोर्ट का विस्तार और आंतरिक सड़कों के जाल को मजबूत करना शामिल है। ऊर्जा के क्षेत्र में हर घर तक बिजली पहुंचाने के अभियान को और तेज किया जाएगा। दूरस्थ गांवों में सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों पर भी काम किया जा रहा है।

शिक्षा व स्वास्थ्य: बस्तर में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए पोटा केबिन स्कूलों के 45 भवनों को स्थायी स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के विस्तार भी तैयार की गई है।

कृषि, सिंचाई व स्टार्टअप:

कृषि और सिंचाई: इंद्रावती नदी पर देवगांव और मटनार में दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 31,840 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है।

स्टार्टअप और रोजगार: युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर देने के लिए राज्य सरकार ने "अजोर विजन 2047" और "विकसित भारत @2047" के तहत स्टार्टअप नीति लागू की है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5,000 स्टार्टअप तैयार करना है। अभी तक एक लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से लगभग 40 हजार युवाओं को रोजगार भी मिल चुका है।

पर्यटन और अन्य पहल

पर्यटन: चित्रकोट और तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, एडवेंचर टूरिज्म, कैनोपी वॉक और प्रस्तावित ग्लास ब्रिज जैसी परियोजनाएं बस्तर को पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने में मदद करेंगी। साथ ही बस्तर ओलंपिक और बस्तर पडुम जैसे आयोजन सांस्कृतिक पहचान को मजबूत कर रहे हैं। बस्तर मुन्ने (अग्रणी बस्तर) कार्यक्रम नक्सलवाद से मुक्त हो रहे बस्तर के गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है।

लाल आतंक का केंद्र अब परिवर्तन का प्रतीक

नक्सलवाद की लंबी कहानी में छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रहा है। कभी देश में नक्सली गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र माने जाने वाले इस इलाके में पिछले वर्षों में लगातार सुरक्षा अभियानों, सड़क और संचार नेटवर्क के विस्तार तथा आत्मसमर्पण नीति के कारण संगठन की जड़ें कमजोर होती गई हैं। परिणामस्वरूप, अब यह क्षेत्र शांति और विकास की एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 31 मार्च 2026 को राज्य के लिए "ऐतिहासिक दिन" बताते हुए कहा कि चार दशकों तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा बस्तर अब विकास की तेज रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त रणनीति, सुरक्षा बलों के साहस और जनता के सहयोग का परिणाम है। मुख्यमंत्री के अनुसार, "जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब विकास, विश्वास और सुशासन की नई धारा बह रही है।" उन्होंने यह भी कहा कि शांति स्थापित होने के बाद बस्तर में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को तेजी से बढ़ाया जाएगा।

नया बस्तर नई सुबह

आज जब बस्तर में बंदूक की आवाज धीरे-धीरे इतिहास बन रही है, तब यह क्षेत्र देश के सामने परिवर्तन की एक नई कहानी प्रस्तुत कर रहा है। चार दशकों तक हिंसा और भय के प्रतीक रहे इस भूभाग में अब विकास, लोकतंत्र और विश्वास की नई नींव रखी जा रही है। 31 मार्च 2026 केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उस लंबे संघर्ष का प्रतीक है जिसमें सुरक्षा बलों के साहस, डबल इंजिन सरकार की रणनीति और स्थानीय समाज के धैर्य ने मिलकर लाल आतंक के दौर को समाप्त कर दिया। इसी ऐतिहासिक मोड़ से शुरू होती है आमचो बस्तर की कवर स्टोरी- "नया बस्तर, नई सुबह", जहां जंगलों की खामोशी अब विकास की नई गूंज में बदल रही है।

- **साय के सुशासन ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का देश में मान**
- **बस्तर के दूरस्थ अंचलों में फूटी विकास की नई धारा**
- **लाल से हरित गलियारे की ओर आमचो बस्तर भूमि**
- **केंद्र का साथ और सुशासन का विश्वास लाया बदलाव**

लाल आतंक का केंद्र अब परिवर्तन का प्रतीक

नक्सलवाद की इस लंबी कहानी में छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रहा। कभी देश में नक्सली गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र माने जाने वाले इस इलाके में पिछले वर्षों में लगातार सुरक्षा अभियानों, सड़क और संचार नेटवर्क के विस्तार तथा आत्मसमर्पण नीति के कारण संगठन की जड़ें कमजोर होती गईं। परिणामस्वरूप अब यह क्षेत्र शांति और विकास की नई यात्रा की शुरुआत कर रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 31 मार्च 2026 को राज्य के लिए "ऐतिहासिक दिन" बताते हुए कहा कि चार दशकों तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा बस्तर अब विकास की तेज रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त रणनीति, सुरक्षा बलों के साहस और जनता के सहयोग का परिणाम है। मुख्यमंत्री के अनुसार, "जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब विकास, विश्वास और सुशासन की नई धारा बह रही है।" उन्होंने यह भी कहा कि शांति स्थापित होने के बाद बस्तर में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को तेजी से बढ़ाया जाएगा ताकि क्षेत्र की युवा पीढ़ी को नई संभावनाएं मिल सकें।

लंबा संघर्ष, निर्णायक परिणाम

1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन से शुरू हुआ माओवादी उग्रवाद धीरे-धीरे देश के कई राज्यों में फैल गया था और 2000 के दशक में यह 180 से अधिक जिलों तक पहुंच गया था। लेकिन पिछले एक दशक में सुरक्षा अभियानों, बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण और शीर्ष नेताओं के खत्म होने से इस आंदोलन की ताकत लगातार घटती गई। बस्तर और दंडकारण्य क्षेत्र में चलाए गए अभियानों में हजारों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, कई गिरफ्तार हुए और बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए। इसके साथ ही सरकार ने पुनर्वास योजनाओं के माध्यम से मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं को नई शुरुआत का अवसर दिया।

शहर सत्ता/रायपुर। लगभग छह दशकों तक भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहे नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष अब एक निर्णायक मुकाम पर पहुंच चुका है। 31 मार्च 2026 को तय समयसीमा के साथ केंद्र सरकार ने संकेत दिया कि देश में वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव निर्णायक रूप से समाप्ति की ओर है। संसद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि दशकों से फैला "रेड कॉरिडोर" अब लगभग समाप्त हो चुका है और जिन क्षेत्रों में कभी माओवादी हिंसा का बोलबाला था, वहां अब विकास की नई धारा बह रही है। लोकसभा में नक्सलवाद पर हुई चर्चा के दौरान गृहमंत्री बोल चुके हैं, पिछले वर्षों में सुरक्षा बलों के निरंतर अभियानों, तकनीक आधारित खुफिया तंत्र और आदिवासी क्षेत्रों में विकास योजनाओं के कारण माओवादी संगठन की शीर्ष नेतृत्व संरचना लगभग ध्वस्त हो चुकी है। उनके अनुसार, देश के कई हिस्सों में फैले इस आंदोलन को सीमित करते हुए सरकार ने इसे कुछ दूरस्थ क्षेत्रों तक समेट दिया और अब वह भी तेजी से समाप्त हो रहा है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी रणनीति के तहत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित अभियान चलाए गए, जिनमें सुरक्षा कार्रवाई के साथ-साथ विकास और पुनर्वास को भी समान महत्व दिया गया।

ऑपरेशन बस्तर: कैसे टूटा नक्सल नेटवर्क

बस्तर में नक्सलवाद का अंत किसी एक अभियान या एक वर्ष की कार्रवाई का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी और बहुस्तरीय रणनीति का नतीजा है। सुरक्षा बलों की सटीक कार्रवाई, आधुनिक तकनीक का उपयोग, प्रशासन की बढ़ती पहुंच और विकास योजनाओं का विस्तार इन सभी ने मिलकर उस नेटवर्क को तोड़ा जो दशकों तक दंडकारण्य के जंगलों में मजबूत बना हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार 2014 के बाद नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति में निर्णायक बदलाव आया। पहले जहां अभियान मुख्य रूप से सुरक्षा कार्रवाई तक सीमित रहते थे, वहीं बाद के वर्षों में "सिक्योरिटी-डेवलपमेंट-ट्रस्ट" के त्रिस्तरीय मॉडल पर काम शुरू हुआ। इसका उद्देश्य केवल नक्सली कैडर को कमजोर करना नहीं, बल्कि उस सामाजिक आधार को भी खत्म करना था, जिस पर यह आंदोलन टिका हुआ था। बस्तर के दूरस्थ इलाकों में सुरक्षा बलों की स्थायी उपस्थिति इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 से 2023 के बीच बस्तर संभाग में 329 सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। इसके बाद 2024 से 2026 के बीच अभियान को और तेज करते हुए 100 से अधिक नए कैंप स्थापित किए गए। इन कैंपों ने न केवल सुरक्षा अभियानों को गति दी, बल्कि उन गांवों तक प्रशासन की पहुंच भी सुनिश्चित की, जहां पहले शासन की मौजूदगी लगभग न के बराबर थी। इन कैंपों के आसपास धीरे-धीरे सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं विकसित होने लगीं, जिससे स्थानीय लोगों का भरोसा भी बढ़ा।

सुरक्षा बलों की प्रमुख सफलताएं

- 2008 से 2025 के बीच कई अभियानों में बड़ी सफलताएं; फरवरी-मार्च 2025 में विभिन्न अभियानों में 31, 26 और 18 नक्सली मारे गए और भारी मात्रा में हथियार बरामद।
- 2018 और 2024 के अभियानों में 8–9 नक्सली ढेर, हथियार और विस्फोटक बरामद।
- 2009 से 2026 तक कई अभियानों में लगातार सफलता; मार्च 2025 में 17 नक्सली तथा जनवरी 2026 में 12 नक्सली मारे गए।
- अप्रैल 2024 में बड़े अभियान में 29 नक्सली मारे गए।
- 2024–2025 के अभियानों में कई बड़ी सफलताएं; अक्टूबर 2024 में 31 नक्सली तथा मई 2025 में शीर्ष माओवादी नेता बसवराजू उर्फ नंबाला केशवराव सहित 27 नक्सली मारे गए।

प्रभावित जिले: बीजापुर | दंतेवाड़ा | सुकमा | कांकेर | नारायणपुर

बस्तर में नक्सल गतिविधियों का आंकड़ा

- बस्तर क्षेत्र में वर्ष 2001 से 2026 तक नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों और प्रशासन को कई महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रमुख स्थिति इस प्रकार रही:
- 3425: पुलिस-नक्सली मुठभेड़
- 1600: मारे गए नक्सली
- 8477: आत्मसमर्पित नक्सली
- 13,637: गिरफ्तार नक्सली
- 3694: बरामद नक्सली हथियार
- 4607: आईईडी बरामद
- 1280: विस्फोट की घटनाएं
- 1318: शहीद सुरक्षा कर्मी
- 1823: नक्सलियों द्वारा मारे गए नागरिक

मुख्य पहलें और रणनीतियां

- सुदूर इलाकों में नए सुरक्षा कैंप स्थापित कर सुरक्षा और विकास को साथ आगे बढ़ाना।
- नियत नेल्लानार योजना के तहत दूरस्थ ग्राम पंचायतों में सतत विकास कार्य।
- बस्तर ओलिंपिक, बस्तर अबूझमाड़ मैराथन और बस्तर हेरिटेज मैराथन जैसे आयोजनों से बदलते बस्तर की सकारात्मक छवि सामने लाना।
- जगदलपुर में पंडुम कैफ़े जैसे नवाचारों के माध्यम से पुनर्वासित माओवादियों और नक्सल हिंसा पीड़ितों को रोजगार उपलब्ध कराना।
- छत्तीसगढ़ पुलिस, CRPF, BSF, ITBP और SSB की संयुक्त कार्रवाई से नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण।

आत्मसमर्पण करने वाले शीर्ष माओवादी

मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ विवेक: पोलित ब्यूरो सदस्य, अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण।
पुल्लुरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रन्ना: केंद्रीय कमेटी सदस्य, अक्टूबर 2025 में तेलंगाना में आत्मसमर्पण।
रामदेव उर्फ सोमा: केंद्रीय कमेटी सदस्य, दिसंबर 2025 में छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण।
टक्कालापल्ली वासुदेव राव उर्फ सतीश: केंद्रीय कमेटी सदस्य, अक्टूबर 2025 बस्तर में आत्मसमर्पण।
थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी: पोलित ब्यूरो सदस्य, फरवरी 2026 में तेलंगाना में आत्मसमर्पण।

बिजली बिल समाधान योजना 2026
28 लाख लोगों को मिलेगी राहत

छत्तीसगढ़ सरकार की 'बिजली बिल समाधान योजना 2026' प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को राहत देने वाली ऐतिहासिक पहल है। इस योजना का उद्देश्य बकाया बिजली बिलों पर छूट और आसान किस्तों की सुविधा देकर आम जनता को आर्थिक बोझ से मुक्त करना है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को तात्कालिक लाभ मिलेगा बल्कि दूरगामी प्रभाव के रूप में ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और भरोसा भी बढ़ेगा। मुख्य मंत्री विष्णु देव साय ने 12 मार्च को रायपुर में इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह योजना आम जनता की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। 757 करोड़ रुपये की राहत सीधे तौर पर उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी। यह योजना घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को विशेष छूट प्रदान करती है। योजना का लाभ इसी वर्ष 30 जून तक उठाया जा सकता है।

सोलर को लेकर उत्साह

प्रदेश में सोलर एनर्जी को लेकर भी लोगों में उत्साह का आलम है। इसका प्रमाण यह है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रति प्रदेश में लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है। अबतक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 36 हजार लोग इससे जुड़ चुके हैं। इसमें खास बात यह भी सामने आ रही है कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सोलर पैनल वेंडर के रूप में कार्य किया जा रहा है जो महिला सशक्तीकरण की एक सकारात्मक पहल है।

हनीट्रैप-2 का राष्ट्रीय ब्लास्ट

छत्तीसगढ़ के DIG समेत 4 राज्यों के रसूखदार जाल में, 100 अश्लील वीडियो से करोड़ों की उगाही

- **इंदौर क्राइम ब्रांच का बड़ा दावा: दिल्ली के नेता से ₹4 करोड़ की थी डील; भोपाल से ऑपरेट हो रहा था ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट**

इंदौर / रायपुर। साल 2019 के कुख्यात सेक्स स्कैंडल की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू हुआ 'हनीट्रैप-2' का ये जाल अब दिल्ली, गुजरात और छत्तीसगढ़ के पावर कॉरिडोर (सत्ता के गलियारों) तक फैल चुका है। इंदौर क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में जो खुलासे हुए हैं, उसने नौकरशाही और राजनीति के शीर्ष पर बैठे लोगों की नींद उड़ा दी है। इस हाई-प्रोफाइल सिंडिकेट के पास से 100 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं, जिनके दम पर नेताओं, नौकरशाहों और उद्योगपतियों को ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपये की रंगदारी वसूली जा रही थी। सबसे चौंकाने वाला नाम छत्तीसगढ़ पुलिस के एक डीआईजी (DIG) रैंक के बड़े अधिकारी का आ रहा है, जिससे रायपुर से लेकर बिलासपुर तक के महकमे में हड़कंप मच गया है।

'डिजिटल डिवाइस' में दफन रसूखदारों के राज

गिरफ्तार आरोपी श्वेता विजय जैन, रेशू चौधरी और अलका दीक्षित से पूछताछ में रोज नए पन्ने खुल रहे हैं। पुलिस ने जब रेशू चौधरी के मोबाइल और अन्य डिजिटल इनपुट खंगाले, तो उसमें रसूखदारों की अश्लील क्लिपिंग्स का पूरा जखीरा मिला।

जांच में सामने आए बड़े टारगेट

छत्तीसगढ़: डीआईजी रैंक के एक कद्दावर आईपीएस अधिकारी।

दिल्ली: एक बेहद सीनियर नेता, जिनसे ₹4 करोड़ वसूलने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था।

मध्य प्रदेश: मालवा-निमाड़ के कुछ रसूखदार नेता, एक सिटिंग विधायक और एक पूर्व आईएएस अधिकारी।

गुजरात: देश के एक बड़े नामी उद्योगपति।

खतरे की घंटी: पुलिस को आशंका है कि ये सिंडिकेट न सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रहा था, बल्कि इन संवेदनशील वीडियो को डार्क वेब या अन्य जगहों पर ऊंचे दामों में बेचने (सौदा करने) की फिराक में भी था।

कॉर्पोरेट स्टाइल में काम: भोपाल था 'हेडक्वार्टर'

यह कोई साधारण गैंग नहीं था, बल्कि इसे पूरी कॉर्पोरेट प्लानिंग के साथ चलाया जा रहा था:

श्वेता विजय जैन (मास्टरमाइंड): भोपाल में बैठकर पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करती थी और बड़े चेहरों की लिस्टिंग करती थी।

रेशू चौधरी (हनीट्रैप फेस): हाई-प्रोफाइल टारगेट्स से संपर्क साधना, उन्हें अपनी बातों में फंसाना और दलदल में खींचने का काम इसका था।

प्रशासनिक शह?: गैंग की पहुंच इतनी थी कि इसमें एक हेड कॉन्स्टेबल विनोद शर्मा और पत्रकार जितेंद्र पुरोहित भी शामिल थे, जो कानूनी और मीडिया के मोर्चे को संभालते थे।

सुपर कॉरिडोर पर मारपीट... और ताश के पत्तों की तरह ढह गया सिंडिकेट

करोड़ों के इस साम्राज्य का अंत तब शुरू हुआ जब लालच में आकर इस गैंग ने हद पार कर दी। इंदौर के बड़े कारोबारी हितेंद्र उर्फ चिंटू ठाकुर को जाल में फंसाकर सुपर कॉरिडोर पर बुलाया गया। 28 अप्रैल को अलका दीक्षित और उसके गुर्गों ने कारोबारी के साथ बेरहमी से मारपीट की और वीडियो वायरल करने के नाम पर मोटी रकम मांगी। कारोबारी ने डरने के बजाय सीधे पुलिस की चौखट पकड़ ली और देखते ही देखते यह पूरा सिंडिकेट बेनकाब हो गया।

छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में 'कानाफूसी' और डर का माहौल

इंदौर से आई इस आंच ने छत्तीसगढ़ के पुलिस मुख्यालय (PHQ) में खलबली मचा दी है। डीआईजी रैंक के किस अधिकारी का वीडियो इंदौर पुलिस के पास है, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। कई अफसर अंदर ही अंदर इस बात से सहमे हुए हैं कि जांच की आंच कहीं उन तक न पहुंच जाए। इंदौर पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि इस सिंडिकेट के पीछे किन बड़े नेताओं और प्रशासनिक अफसरों का वरदहस्त (संरक्षण) था, जिसके दम पर यह गैंग बेखौफ होकर चार राज्यों में समानांतर सरकार चला रहा था।

रायपुर प्रेस क्लब की विस्तारित कार्यकारिणी एवं प्रकोष्ठ संयोजकों की बैठक सम्पन्न

पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे, गौरव मार्तंड उत्सव की तैयारियां तेज

शहर सत्ता/रायपुर। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा 30 मई को आयोजित किए जा रहे "पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव" की तैयारियों को लेकर आज प्रेस क्लब परिसर में महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने सबसे पहले प्रेस क्लब कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक ली। बैठक में कार्यकारिणी के नव नियुक्त सात सदस्यों के साथ विभिन्न मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के विशेष आमंत्रित संयोजक तथा सलाहकार सदस्य के रूप में प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व महासचिव भी उपस्थित रहे। कार्यकारिणी की बैठक के पश्चात "पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव" के सफल आयोजन हेतु गठित विभिन्न समितियों की अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में संरक्षक एवं सलाहकार मंडल के सदस्यों ने विभिन्न समितियों के संयोजकों के साथ आयोजन की रूपरेखा, कार्यक्रम के स्वरूप तथा आयोजन की सफलता को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित यह विशेष उत्सव दिनभर चार सत्रों में संपन्न होगा।

कार्यक्रम का प्रथम सत्र शुभारंभ सत्र होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्य एवं जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। द्वितीय सत्र हिंदी प्रिंट मीडिया की 200 वर्षों की गौरवशाली यात्रा एवं उसकी भूमिका पर केंद्रित रहेगा। तृतीय सत्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं न्यू मीडिया की संभावनाओं और चुनौतियों पर आधारित होगा, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ एवं विभिन्न संस्थानों से जुड़े प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे। इसके अतिरिक्त रायपुर प्रेस क्लब द्वारा इस अवसर पर एक विशेष सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पत्रकार साथियों की प्रस्तुतियों के साथ संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, संयुक्त सचिव निवेदिता साहू एवं भूपेश जांगड़े सहित कार्यकारिणी एवं विभिन्न समितियों के सदस्य उपस्थित रहे। रायपुर प्रेस क्लब ने सभी पत्रकार साथियों, मीडिया संस्थानों एवं नागरिकों से इस ऐतिहासिक आयोजन में सहभागिता की अपील की है।

उत्सव के बाद होंगे क्लब हितार्थ कई पेंडिंग फैसले

रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी एवं महासचिव गौरव शर्मा और कार्यकारिणी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के पश्चात् राजधानी रायपुर प्रेस क्लब के बहुप्रतीक्षित मतदाता सूचि अपडेट करने, नई मेंबरशिप और पूरवर्ती कार्यकाल के पेंडिंग मामलों के निराकरण का आश्वासन दिया है। प्रेस क्लब रायपुर के आय-व्यय संबंधी कार्यों पर अपनी पैनी नजर रखने वाले कोषाध्यक्ष दिनेश यदु ने भी भरोसा दिलाया है कि समय पर चुनाव, नए मतदाताओं की सदस्यता और वर्ष 2017 के बाद अपडेट नहीं की गई मतदाता सूचि को एक वर्षीय कार्यकाल के भीतर ही निराकृत करने का प्रयास किया जायेगा।

वर्ष 2017 के बाद से नहीं हुई है अब तक लिस्ट अपडेट

तात्कालीन अध्यक्ष केके. शर्मा के कार्यकाल वर्ष 2017 के बाद से ही रायपुर प्रेस क्लब की वोटर लिस्ट अपडेट नहीं की

गई है। पूर्व अध्यक्ष दामू अम्बेडारे 5 वर्षों तक रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने रहे और इन्हें हराकर अध्यक्ष पद पर प्रफुल्ल ठाकुर ने 19 महीने सफलता पूर्वक कार्य किया। इन्हीं के कार्यकाल में मतदाता सूचि में गलत कांट-छाट करने, असंवैधानिक तरीके से नए मतदाता जोड़ने और सदस्यता शुल्क 1000 रूपये से लेकर 500 रूपये के हिसाब को लेकर हिसाब-किताब लेना नई कार्यकारिणी के लिए बड़ी चुनौती है।

देखा जाये तो 2017 के पूर्ववर्ती कार्यकाल और 2017 के पश्चात् निर्वाचित कार्यकालों ने निर्धारि एक वर्ष में क्लब का चुनाव नहीं करवा पाया है। फ़िलहाल वर्तमान प्रेस क्लब कार्यकारिणी तकरीबन साढ़े चार माह में कई ऐतिहासिक आयोजन की सूत्रधार रही है। लेकिन रायपुर प्रेस क्लब के हितार्थ आवश्यक कार्यों को करना बाकि है।

छत्तीसगढ़ वन विभाग में ₹14.77 लाख की धोखाधड़ी, कैम्पा प्रभारी नपे

कागजों पर उग आए पौधे, फर्जी दस्तावेजों से ठिकाने लगा दिए सरकारी पैसे

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जहां एक ओर सरकारें पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रही हैं, वहीं दूसरी ओर विभागीय अफसर और बाबू 'गोबर खाद' जैसी बुनियादी चीजों में भी सेंध लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मरवाही वनमंडल से भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वृक्षारोपण के नाम पर ₹14.77 लाख का 'गोबर खाद घोटाला' कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है और मुख्य आरोपी कैम्पा (CAMPA) शाखा प्रभारी व सहायक ग्रेड-02 भूपेंद्र कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया है।

कूट रचित दस्तावेज और 'अंधेरे' में अफसर

यह पूरा मामला साल 2022 के वृक्षारोपण अभियान से जुड़ा है। जांच में जो बातें सामने आई हैं, वे बेहद चौंकाने वाली हैं:

फर्जी प्रमाण पत्र: आरोपी भूपेंद्र कुमार साहू ने खाद खरीदी के नाम पर फर्जी और कूट रचित (Forged) दस्तावेज तैयार किए।

अफसरों को रखा गुमराह: चालाकी से वनमंडलाधिकारी (DFO) को पूरी तरह अंधेरे में रखा गया और फर्जी सर्टिफिकेट्स के दम पर एलओसी (LOC - Letter of Credit) जारी करवा ली गई।

₹14.77 लाख का गबन: इन फर्जी कागजातों के सहारे कुल $14,77,600$ रुपये का अवैध लेखा-जोखा तैयार कर शासकीय धन को ठिकाने लगा दिया गया।

जांच में भी अड़ंगा: जब इस वित्तीय अनियमितता की शिकायतें बढ़ीं और जांच शुरू हुई, तब भी आरोपी बाबू द्वारा जांच टीम को भ्रामक जानकारी देकर गुमराह करने और लापरवाही बरतने की कोशिश की गई।

आचरण नियमों की धज्जियां उड़ीं

भूपेंद्र कुमार साहू का यह कारनामा 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3' का खुला उल्लंघन पाया गया। इसके बाद विभाग ने उन पर निलंबन की गाज गिरा दी।

निलंबन के कड़े नियम

मुख्यालय में तब्दीली: निलंबन की अवधि के दौरान साहू का मुख्यालय 'कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त' तय किया गया है।

नो-एंट्री बिना इजाजत: बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के वे अपना यह नया मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

सिर्फ गुजारा भत्ता: इस पूरी अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) ही दिया जाएगा।

अब 'विशेष बच्चों' को पढ़ाने के लिए TET अनिवार्य; सुप्रीम कोर्ट का फरमान

नई दिल्ली/रायपुर। देशभर के दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Special Children) की शिक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक युगांतकारी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब सामान्य शिक्षकों की तरह विशेष शिक्षकों (Special Educators) को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। जस्टिस की पीठ ने इस मामले की 'इनसाइड स्टोरी' को खंगालते हुए साफ किया कि विशेष बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकारों की सुस्त कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर 'डेडलाइन' तय कर दी है। अदालत ने राज्यों की रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद अलग-अलग और कड़े निर्देश जारी किए हैं:

छत्तीसगढ़ सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य में 49,000 से अधिक विशेष बच्चे हैं, जिनके लिए अनुमानित 3,981 पदों की जरूरत है। वर्तमान में 848 पद स्वीकृत हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्राथमिक स्तर पर संविदा पर कार्यरत 155 ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों और माध्यमिक स्तर के 85 विशेष शिक्षकों को अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश होना होगा। योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की यह प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी। इसके बाद ही सरकार नए पदों के विज्ञापन जारी कर सकेगी।

'जुलाई 2026' में खुलेगा प्रोग्रेस रिपोर्ट का लिफाफा

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी व्यवस्था को केवल कागजों तक सीमित रखने से मना कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि तीनों राज्य सरकारें इस पूरी भर्ती और स्क्रीनिंग प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाएं। जुलाई 2026 में जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी, तब सभी राज्यों को अपनी 'कार्रवाई रिपोर्ट' (Action Taken Report) कोर्ट के टेबल पर प्रस्तुत करनी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) के पिछले हलफनामे के आलोक में, वर्तमान में संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग के दौरान टीईटी उत्तीर्ण होना एक 'वांछनीय योग्यता' (Desirable Qualification) माना जाएगा, लेकिन भविष्य की नियुक्तियों में इस शर्त से कोई समझौता नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बस्तर एनकाउंटर की SIT जांच वाली याचिका की खारिज

नई दिल्ली / बस्तर। "जंगल की लड़ाई बेहद मुश्किल होती है। एक कट्टर नक्सली, जिसके पास से अत्याधुनिक हथियार मिले हों, सुरक्षाबल उसका स्वागत गुलदस्ते से नहीं कर सकते।" छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुए एक बड़े नक्सली एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बेहद तल्ख और ऐतिहासिक टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने माओवादी कमांडर कथा रामचंद्र रेड्डी के बेटे राजा चंद्र द्वारा दायर उस याचिका (SLP) को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें बस्तर के जंगलों में हुई मुठभेड़ को 'फर्जी' बताते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से जांच कराने की मांग की गई थी। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ (बिलासपुर) हाई कोर्ट के उस आदेश पर मुहर लगा दी है, जिसने दोबारा पोस्टमार्टम और जांच से इनकार कर दिया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की डिवीजन बेंच के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि रेड्डी के शरीर पर कई चोटों के निशान थे।

सैलरी में देरी बर्दाश्त नहीं, राजस्व वसूली में लापरवाही पर अल्टीमेटम

बिलासपुर में सचिव शंगीता आर. की बड़ी समीक्षा

रायपुर / बिलासपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने मैदानी स्तर पर व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए बिलासपुर में मोर्चा संभाल लिया है। बिलासपुर नगर निगम और जिले के सभी नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक के दौरान सचिव ने सख्त रुख अपनाते हुए दो टूक कहा कि कर्मचारियों का वेतन और जनता के विकास कार्यों में किसी भी तरह की लेत-लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमांड एंड Control सेंटर में हुई इस हाई-प्रोफाइल बैठक में सचिव ने वित्तीय अनुशासन से लेकर जमीनी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने की नई समय-सीमा (Deadlines) तय कर दी है।

वेतन पहली प्राथमिकता

सचिव शंगीता आर. ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा और निकायों की आर्थिक स्थिति को लेकर बड़े निर्देश दिए:

महीने के पहले हफ्ते में सैलरी: चाहे नियमित कर्मचारी हों या प्लेसमेंट वाले, सभी का वेतन हर हाल में महीने के प्रथम सप्ताह में हो जाना चाहिए।

₹15 करोड़ की वसूली का अल्टीमेटम: वित्तीय वर्ष 2025-26 के बकाया 15 करोड़ रुपये के राजस्व को वसूलने के लिए दिसंबर 2026 की आखिरी डेडलाइन तय की गई है। उन्होंने साफ कहा कि राजस्व ही किसी भी निकाय की रीढ़ है, इसमें शत-प्रतिशत रिकवरी चाहिए।

टेंडर और प्रोजेक्ट्स की सुस्ती पर प्रहार

सरकारी कामों में होने वाली कागजी देरी को खत्म करने के लिए सचिव ने नए दिशा-निर्देश जारी किए:

ठेकेदारों से तुरंत अनुबंध: टेंडर की मियाद खत्म होते ही ठेका पाने वाली एजेंसी से तुरंत एग्रीमेंट कर काम शुरू कराया जाए। टेंडर प्रक्रिया में लगने वाले अत्यधिक समय का विश्लेषण कर सिस्टम को तेज करने की योजना बनाने को कहा गया है।

कोनी चार्जिंग स्टेशन के लिए 1 महीना: पीएम ई-बस सेवा के लिए कोनी में बन रहे चार्जिंग स्टेशन और बस डिपो को एक महीने के भीतर पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है।

'आदर्श वार्ड' बनाने वाले नोडल अफसर होंगे सम्मानित : वार्डों की सूरत बदलने के लिए सचिव ने अनोखी पहल की है। निगम के वार्ड नोडल अफसरों को अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों को 'आदर्श वार्ड' (सड़क, पानी, बिजली और उत्कृष्ट सफाई युक्त) बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बेहतर काम करने वाले अफसरों को विभाग सम्मानित करेगा।

डीजल की किल्लत और मंदी की मार

धमधा में 500 एकड़ में खड़ी पपीते की फसल पर किसानों ने चलाया ट्रैक्टर

दुर्ग-भिलाई (धमधा)। कहा जाता है कि किसान का खून-पसीना जब जमीन पर गिरता है, तब फसल लहलहाती है। लेकिन जब वही किसान अपनी ही गाढ़ी कमाई और महीनों की मेहनत से तैयार लहलहाती फसल पर खुद अपने हाथों से ट्रैक्टर चलाने को मजबूर हो जाए, तो समझ जाइए कि सिस्टम आईसीयू (ICU) में है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र से एक ऐसी ही झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पपीता उत्पादक किसानों ने करीब 500 एकड़ में लगी तैयार फसल को ट्रैक्टर से रौंदकर नष्ट कर दिया। इस तबाही के पीछे दो मुख्य विलेन रहे—बाजार की मंदी (ओवर-प्रोडक्शन) और एन वक्त पर खड़ा हुआ 'डीजल संकट', जिसने रही-सही कसर पूरी कर दी।

बंपर पैदावार बनी अभिशाप

पिछले साल बाजार में पपीते के बेहतरीन दाम (18 से 20 रुपये किलो) मिले थे। इसी मुनाफे की उम्मीद में इस साल धमधा के किसानों ने बड़े पैमाने पर पपीते की खेती कर दी। नतीजा यह हुआ कि उत्पादन उम्मीद से ज्यादा (बंपर) हो गया। बाजार में पपीते की भारी आवक होते ही व्यापारी गायब हो गए। जो पपीता पिछले साल ₹20 किलो था, वह इस पूरे सीजन में 6 से 7 रुपये किलो के बीच सिमट कर रह गया। लागत निकालना भी दूभर हो गया।

'डीजल संकट' का डबल अटैक

धमधा का कच्चा पपीता केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली की बड़ी मंडियों तक सप्लाई होता है। लेकिन इस बार प्रदेश में गहराए अचानक 'डीजल संकट' ने रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी: डीजल की किल्लत के चलते ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप हो गई। गाड़ियां नहीं मिलने से माल मंडियों तक नहीं पहुंच सका। जो पपीता कच्चा ही बाहर भेजा जाना था, वह पौधों पर ही पकने और सड़ने लगा।

किसानों की आपबीती

किसान जालम सिंह पटेल: 10 एकड़ की खेती में ₹10 लाख की लागत आई थी, लेकिन पूरे सीजन में सिर्फ ₹7 लाख की ही बिक्री हो पाई। यानी सीधे ₹3 लाख की चपत।

किसान डिलेश्वरी वर्मा (पथरीकला): 20 एकड़ के खेत में 16,500 पौधों पर 80 टन पपीता बिल्कुल तैयार खड़ा था। डिलेश्वरी कहती हैं कि सिर्फ ₹2 किलो का भी मुनाफा मिल जाता तो ₹1.80 लाख घर आते, लेकिन खरीदार न मिलने से फसल को रौंदना पड़ा।

किसान शिवकुमार वर्मा: 50 एकड़ और विवेक वर्मा ने 15 एकड़ में लगी लहलहाती फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया।

संपादकीय

• सुकांत राजपूत

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और डगमगाती बुनियाद

किसी भी जीवंत लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के साथ-साथ पत्रकारिता को 'चौथा स्तंभ' माना गया है। इस स्तंभ की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज के प्रति कितना जवाबदेह है, सत्ता से कितने कड़े सवाल पूछ सकता है और बिना किसी पक्षपात के सच को सामने लाने की कितनी हिम्मत रखता है। लेकिन आज के डिजिटल और व्यावसायिक युग में, पत्रकारिता के बदलते मापदंड और इसके तेजी से गिरते नैतिक मूल्य बेहद चिंता का विषय बन चुके हैं।

पारंपरिक पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य 'सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना' था। आज यह उद्देश्य बदलकर 'सनसनी फैलाना, ध्यान भटकाना और टीआरपी बटोरना' हो गया है। गंभीर और जन-सरोकार से जुड़े मुद्दों—जैसे बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण भारत की समस्याएं—को हाशिए पर धकेल दिया गया है। उनकी जगह प्राइम-टाइम पर होने वाली ऐसी चिल्लाहट भरी बहसों ने ले ली है, जिनका मकसद किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं, बल्कि समाज में ध्रुवीकरण पैदा करना होता है। आज मीडिया घराने बड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों और राजनीतिक दलों के आर्थिक हितों से संचालित हो रहे हैं। जब मीडिया का मुख्य स्रोत केवल विज्ञापन बन जाता है, तो उसकी निष्पक्षता दम तोड़ देती है। 'पेड न्यूज' (Paid News) से शुरू हुआ यह खेल अब 'एजेंडा पत्रकारिता' तक पहुंच चुका है। पत्रकार अब निष्पक्ष रेफरी की भूमिका में नहीं, बल्कि किसी एक पक्ष के प्रवक्ता के रूप में नजर आते हैं। सत्ता से सवाल पूछने की जो हिम्मत कभी पत्रकारिता की पहचान हुआ करती थी, वह अब सत्ता की चाटुकारिता और विपक्ष से सवाल पूछने की अजीब परिपाटी में बदल चुकी है। तकनीक के विस्तार ने जहां सूचनाओं का लोकतांत्रीकरण किया है, वहीं पत्रकारिता के मापदंडों को सबसे ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। 'सबसे पहले' खबर देने की अंधी दौड़ में खबरों की सत्यता जांचने (Fact-check) की बुनियादी प्रक्रिया को छोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया पर क्लिकबेट (Clickbait) संस्कृति और व्यूज (Views) पाने की लालसा ने सनसनीखेज हेडलाइंस को जन्म दिया है। इसके कारण 'फेक न्यूज' और भ्रामक जानकारियां समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। मीडिया की सबसे बड़ी पूंजी उसकी 'विश्वसनीयता' होती है। जब पाठक या दर्शक का मीडिया से भरोसा उठ जाता है, तो वह केवल एक चैनल या अखबार नहीं खोता, बल्कि लोकतंत्र अपनी सबसे मजबूत ढाल खो देता है।

पत्रकारिता को इस आत्मघाती रास्ते से वापस लौटना होगा। आत्ममंथन का यह समय केवल पत्रकारों के लिए नहीं, बल्कि पाठकों और दर्शकों के लिए भी है। हमें सनसनीखेज खबरों को नकारना होगा और गंभीर पत्रकारिता का समर्थन करना होगा। डिजिटल युग के इस दौर में यदि पत्रकारिता को अपनी साख बचानी है, तो उसे तकनीक को तो अपनाना होगा, लेकिन अपने पुराने नैतिक मूल्यों—जैसे निष्पक्षता, सत्यता और जन-कल्याण—को वापस अपनी रीढ़ बनाना होगा। अन्यथा, यह चौथा स्तंभ केवल कागजी बनकर रह जाएगा।

उदंत मार्तण्ड से उदंत मार्केट तक पत्रकारिता

हरिदास/रायपुर

हिन्दी पत्रकारिता के दो सौ साल पूरे हो गए। यह कम उपलब्धि नहीं है। दो सौ साल में आदमी लगभग दो से तीन बार फिर से जन्म ले कर अपना एक पैर कब्र में रख चुका होता है, अनेक संस्थाओं का तो नामो-निशान मिट जाता है और विचारधाराएँ भी अपना दल बदल लेती हैं, मगर हिन्दी पत्रकारिता अभी भी जीवित है। हालांकि उसे पहचानने के लिए कहीं-कहीं पर आधार कार्ड लग सकता है।

कोलकाता के प्रसिद्ध बड़ा बाजार के समीप, 37, अमर तल्ला लेन, कोलूटोला से 30 मई, 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' शुरू हुआ था। इसकी नींव रखी थी पं. जुगल किशोर शुक्ल जी ने। उन्होंने उस ब्रिटिश दौर में कठिन संघर्ष किया था। इतिहास के पन्नों में अनेक बाते दर्ज हैं। विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों से परीक्षा में अब इस पर सवाल पूछा जाना भी लगभग बंद हो गया है। सवाल बनाने वाले मूर्धन्यगण भी उदन्त मार्तण्ड शब्द के अर्थ से अनभिज्ञ रहते हैं। हिन्दी पत्रकारिता के साथ ही हिन्दी के पत्रकारों का संघर्ष भी बीते 200 वर्षों से जारी है। स्व. जुगल किशोर शुक्ल और भारतेंदु हरिशचंद्र की आत्मा आज यह देखकर कलप रही होगी कि हिन्दी पत्रकारिता खबरों से ज्यादा "एक्सक्लूसिव", "बिग ब्रेकिंग" जैसे विशेषणों का उत्पादन कर रही है। पहले अखबार जनता को बताता था कि देश में क्या हो रहा है। अब चैनल जनता को बताते हैं कि देश को किस बात पर नाराज़, गर्वित, भयभीत और भावुक होना चाहिए। पहले पत्रकार सत्ता से असुविधाजनक प्रश्न पूछता था। आजकल कई पत्रकार सत्ता से इतने विनम्र प्रश्न पूछते हैं कि प्रश्न कम, सरकारी धन्यवाद ज्ञापन ज्यादा लगते हैं। कुछ एंकरों ने निष्पक्षता को ऐसे त्यागा है जैसे नेता चुनाव बाद घोषणा-पत्र को त्यागता है।

हिन्दी पत्रकारिता ने दो सौ साल में बड़ी छलांग लगाई है। पहले खबर के पीछे रिपोर्टर भागता था, अब रिपोर्टर के पीछे टीआरपी, एल्गोरिद्म और मालिक का व्हाट्सऐप संदेश भागता है। न्यूजरूम अब समाचार कक्ष कम, ध्वनि प्रदूषण प्रयोगशाला अधिक लगते हैं। पाँच लोग एक साथ चिल्लाते हैं, स्क्रीन आठ हिस्सों में बँटती है, नीचे पट्टी भागती है, ऊपर राष्ट्र भागता है और बीच में कहीं खबर दम तोड़ देती है। आज हिन्दी पत्रकारिता में सत्य वही है जो प्राइम टाइम तक टिक जाए। विचार वही है जो ट्रेंड कर जाए। और राष्ट्रहित वही है जिसे स्पॉन्सर आपत्ति न करे। हिन्दी पत्रकारिता भले ही आक्सीजोन की शरण में हो, लेकिन समस्याएँ दो सौ साल से हृष्ट-पुष्ट हैं, तब पाठक कम थे और आज खबरें कम लेकिन चैनल ज्यादा हैं। इसलिए एक ही खबर को दिन भर चबाने, तलने, भुनने के बाद रात नौ बजे राष्ट्रवाद की चटनी लगाकर परोसा जाता है। पहले पत्रकारिता में "समाचार" होता था। अब "नैरेटिव" होता है। आज का न्यूजरूम बड़ा लोकतांत्रिक है। वहाँ हर किसी को बोलने की आज़ादी है, बशर्ते वह मालिक, मार्केटिंग विभाग, राजनीतिक समीकरण, विज्ञापनदाता और टीआरपी की भावना के अनुकूल बोले। बाकी जो चमकता दिख रहा होता है, वह पत्रकारिता कम, स्टूडियो-निर्मित राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव ज्यादा लगता है। अखबारों की हालत भी कम रोचक नहीं। पहले संपादकीय पढ़कर पाठक की सोच बना करती थी। अब कई बार पाठक पहले यह सोचता है कि यह खबर है, विज्ञापन है या किसी की पीआर एजेंसी की साहित्यिक अभिव्यक्ति। ऊपर से अंग्रेजी के शब्दों के तड़के के बिना हिन्दी के अखबारों का भी काम नहीं चलता। विडंबना देखिए — हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर सबसे ज्यादा पोस्ट अंग्रेज़ी फॉन्ट में लिखी जाती हैं—"Hindi Patrakarita Diwas ki hardik wishes!"

खैर...हिन्दी पत्रकारिता दिवस के दो सौ वर्ष पूरे होने पर अनेक समारोह होंगे, सेमिनार होंगे, स्मारिका निकलेगी, वक्तव्य होंगे। हमेशा की तरह संकल्प लेंगे तोड़े जाने के लिए और फिर मिलेंगे अगली बरसी पर...फिर भी उम्मीद बाकी है। क्योंकि अभी भी कहीं कोई पत्रकार जिला अस्पताल की बदहाली लिख रहा है, कोई किसान की आत्महत्या की खबर भेज रहा है, कोई आदिवासी गाँव की प्यास को शब्द दे रहा है। हिंदी पत्रकारिता अभी भी कहीं किसी छोटे कस्बे के रिपोर्टर की टूटी मोटरसाइकिल में सांस ले रही है; किसी फ्रीलांसर की बकाया भुगतान वाली फ़ाइल में पड़ी है; किसी जिला संवाददाता की जेब में रखी पुरानी डायरी में जिंदा है। उन सभी को साधुवाद जिन्होंने बिना किसी हिंग्लिश और क्लिष्ट शब्दों के हिन्दी पत्रकारिता को बचाए रखा है। हिन्दी पत्रकारिता दिवस के 200 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं...

राजनीतिक प्रबंधन दूर करेगा संकट

जूही पाठक

भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है। हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और औद्योगिक प्रगति के तहत ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति पर टिकी हुई है। आज की तारीख में भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग पचासी प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है। यह भारी-भरकम आयात न केवल देश के राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है, बल्कि भारत की विदेश नीति और आर्थिक निर्णयों में भी बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में भविष्य पर विचार करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईंधन व्यवस्था की दृष्टि से भारत के मौजूदा तेल स्रोत क्या हैं और आने वाले भविष्य में देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर क्या संभावनाएं और चुनौतियां छिपी हैं।

भारत का घरेलू तेल उत्पादन मुख्य रूप से तीन प्रमुख हिस्सों में बंटा हुआ है, जिनमें तटीय तेल क्षेत्र, उथले अपतटीय क्षेत्र और गहरे तथा अति-गहरे अपतटीय तेल क्षेत्र शामिल हैं। तटीय यानी जमीन पर स्थित तेल स्रोतों में राजस्थान का बाड़मेर ब्लॉक सबसे महत्वपूर्ण है, जहां मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या जैसे तेल क्षेत्र देश के घरेलू कच्चे तेल उत्पादन में अहम योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा असम के डिगबोई, नाहरकटिया और मोरान-हुगरीजान जैसे पारंपरिक क्षेत्र आज भी देश को तेल की आपूर्ति कर रहे हैं, जबकि गुजरात के अंकलेश्वर और कच्छ क्षेत्र भी प्रमुख ऑनशोर तेल स्रोत बने हुए हैं। भारत का तेल परिदृश्य एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत सरकार रूप से चार रणनीतिक मोर्चों पर आगे बढ़ रही है, जिसमें सबसे पहला मोर्चा गहरे और अति-गहरे समुद्र में नए भंडारों की खोज का है। भारत सरकार ने ओपन-एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, मदद्री बेसिन और गैस बाजार के विशाल क्षेत्रों को पुराने कैद नियमों से मुक्त कर दिया है ताकि इन अनछुए क्षेत्रों का दोहन किया जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण मोर्चा सामरिक तेल भंडारों का विस्तार है, ताकि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध या आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की स्थिति में देश की ईंधन व्यवस्था ठप न हो। वर्तमान में विशाखापत्तनम, मंगलोर और पादुर में सामरिक पेट्रोलियम भंडार के रूप में संग्रहीत तेल कच्चे तेल आपातकाल के लिए सुरक्षित रखा गया है और भविष्य की योजना के तहत ओडिशा के चांदीखोल तथा पादुर के दूसरे चरण में इस क्षमता को दोगुना किया जा रहा है। ईंधन व्यवस्था के दृष्टिकोण से भारत का भविष्य काफी हद तक रणनीतिक प्रबंधन पर निर्भर करता है। एक तरफ जहां घरेलू रूप से गहरे समुद्र में नए कुओं की खोज और सामरिक तेल भंडारों को सुरक्षित करना देश की वर्तमान जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ तेल पर निर्भरता घटाकर वैकल्पिक ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाना भारत का अंतिम लक्ष्य है। जब तक देश ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, तब तक कच्चे तेल के स्रोतों का रणनीतिक प्रबंधन ही भारत के विकास के पहियों को बनाए रखने की महत्वपूर्ण कुंजी है।

साप्ताहिक शहर सत्ता

हीटवेव की चपेट में भारत

प्रचंड गर्मी की वजह से तापमान 47 डिग्री पार, कब मिलेगी राहत?

नई दिल्ली। भारत के कई हिस्सों में इस वक्त भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. देश के कई राज्यों में प्रचंड गर्मी की वजह से तापमान 47 डिग्री के पार हो गया है, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, देश के मध्य भागों, उससे सटे उत्तर प्रदेश, पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.

वहीं, भारत के पूर्वोत्तर हिस्से, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और पश्चिम-दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा. जबकि भीषण गर्मी के बीच विदर्भ के ब्रह्मपुरी सबसे ज्यादा तपता हुआ इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और कई राज्यों में लू जैसे हालात बने हुए हैं. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है. लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपनी ताजा बयान में कहा है कि रविवार को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिलाजुला असर देखने को मिला।. आईएमडी ने कहा कि रविवार को कहीं भीषण गर्मी और लू लोगों को परेशान करेगी, तो कहीं बारिश और बादलों की मौजूदगी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने संकेत दिया कि देश के कई राज्यों में तापमान और बारिश का यह असमान पैटर्न जारी रहेगा.

कहां-कहां भीषण गर्मी का दिखेगा प्रकोप?

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में गर्मी का सबसे ज्यादा रहने की संभावना है. कई इलाकों में लू चल सकती है और तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में भी उमस और गर्म हवा के कारण लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है. मौसम विभाग ने इन इलाकों के लिए हीटवेव और भीषण गर्मी के लिए अलर्ट जारी किया है. हालांकि, इस भीषण गर्मी और लू की स्थिति में सुधार को लेकर मौसम विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में सबसे ज्यादा 47.2 टेंपरेचर

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को चेतावनी दी कि मध्य भारत में मई के आखिर तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले चार से पांच दिनों के दौरान केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

केरल कब तक पहुंचेगा मानसून?

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून शनिवार को दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पूर्वी अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के अलावा अंडमान सागर के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है. पूर्वानुमान के अनुसार केरल में मानसून 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें 4 दिनों की देर हो सकती है हालांकि मानसून के आगमन की सामान्य तारीख 1 जून है. उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 45-47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी हिमालय को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. विदर्भ के ब्रह्मपुरी में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ इलाकों में 29 मई तक लू चलने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में 29 मई तक लू चलने की आशंका है और कुछ इलाकों में 27 मई तक भीषण लू चलने की आशंका है.

फाल्टा उपचुनाव में भाजपा की जीत देबांगशु ने तोड़ा रिकॉर्ड

नई दिल्ली। केरल में यूडीएफ ने बहुमत हासिल किया, लेकिन सीएम के ऐलान में काफी समय लगा दिया. इससे

पहले गुरुवार यानी 14 मई को केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस ने वीडी सतीशन के नाम पर मोहर लगाई. अब उनके शपथ ग्रहण से जुड़ी जानकारी सामने आई है. खुद वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. केरल के मुख्यमंत्री पद नामित वीडी सतीशन का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे (18 मई 2026) होगा. मुख्यमंत्री के साथ-साथ लगभग 6 दशकों के बाद पूरी कैबिनेट एक साथ शपथ लेगी. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. कांग्रेस के 63 विधायकों में कई काबिल नेता हैं. कई काबिल नेताओं को बाहर भी रखा गया है. वे कैबिनेट से बाहर ही रहेंगे. इसमें दुख और कठिनाई है. विभिन्न सीमाओं, मानदंडो और सामाजिक वास्तविकताओं के कारण ऐसे निर्णय लिए गए हैं.केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतात्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ ने 140 सीटों में से 102 सीटें जीतीं थीं.।

डीएमके और कांग्रेस गठबंधन में बड़ी दरार!

- **उदयनिधि स्टालिन बोले- 'कांग्रेस ने किया विश्वासघात, अब कभी नहीं...'**

नई दिल्ली। DMK नेता और पार्टी की यूथ विंग के सचिव उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने तमिलगा वेत्री कझगम (T V K) की अल्पमत सरकार का समर्थन करके DMK के साथ विश्वासघात किया है. एक पार्टी कार्यक्रम में उदयनिधि ने कहा कि अब DMK को कांग्रेस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने DMK कार्यकर्ताओं की मेहनत और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की लोकप्रियता की वजह से चुनाव जीता, लेकिन बाद में बिना जानकारी दिए गठबंधन छोड़ दिया.

उदयनिधि स्टालिन ने कहा, 'DMK कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से कांग्रेस के पांच विधायक जीत पाए. लोगों ने कांग्रेस को वोट इसलिए दिया क्योंकि वे एमके स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे. लेकिन आज कुछ पदों के लिए कांग्रेस हमें बताए बिना चली गई. ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जिनमें बुनियादी आभार और शालीनता नहीं है.' उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी.

देश में BJP की बढ़त की वजह कांग्रेस

उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस को पूरे देश में BJP की मजबूती के लिए भी जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह BJP की जीत की मुख्य वजह हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि कांग्रेस की राजनीति ने BJP को मजबूत किया है. उन्होंने कहा, 'हमारे नेता एमके स्टालिन ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को अपने कंधों पर उठाया था, लेकिन कांग्रेस ने उसका सम्मान नहीं किया.' DMK की बैठक में कांग्रेस के खिलाफ कई कड़े प्रस्ताव भी पारित किए गए. पार्टी नेताओं ने कांग्रेस को पीठ में छुरा घोंपने वाला और जोंक तक कहा. आरोप लगाया गया कि कांग्रेस अपने सहयोगियों की मेहनत पर राजनीति करती है।

नीट पेपर लीकः CBI का पुणे में मनीषा के घर पर छापा!

नई दिल्ली। NEET पेपर लीक मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है. इसी कड़ी मेंCBI ने पुणे से गिरफ्तार फिजिक्स टीचर मनीषा हवलदार के घर पर छापेमारी की. जांच के दौरान कई अहम जानकारी सामने आई हैं, जिनसे मामले में बड़े नेटवर्क के होने की आशंका बढ़ गई है.सूत्रों के मुताबिक, मनीषा हवलदार ने कुछ हैंड रिटेन यानी हाथ से लिखे गए प्रश्नपत्र तैयार किए थे. जांच एजेंसियों को शक है कि इन प्रश्नपत्रों को बाद में सबूत मिटाने के लिए जला दिया गया. CBI अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये प्रश्नपत्र किन लोगों तक पहुंचाए गए थे और इसमें और कौन-कौन शामिल था. जांच में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है. मनीषा हवलदार के पति के मोबाइल फोन में GOD नाम से सेव एक नंबर मिला है. जांच एजेंसियों को इस नंबर से हुई कई संदिग्ध बातचीत के संकेत मिले हैं. CBI अब यह जानने में जुटी है कि आखिर GOD नाम से सेव यह व्यक्ति कौन है और उसका इस पूरे पेपर लीक मामले में क्या रोल है।

यूएन में तीसरे राउंड की बातचीत भी फेल

न्यूक्लियर डील पर फिर आमने-सामने अमेरिका-ईरान

संयुक्त राष्ट्र में परमाणु अप्रसार संधि (NPT) को लेकर हुई तीसरे दौर की समीक्षा वार्ता बिना किसी अंतिम समझौते के समाप्त हो गई. इसके बाद ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर 'अड़ंगा डालने' का आरोप लगाया. ईरान ने कहा कि अमेरिकी दबाव और अत्यधिक मांगों की वजह से यह महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन लगातार तीसरी बार किसी अंतिम दस्तावेज को अपनाने में विफल रहा है.

ईरान का अमेरिका पर सीधा हमला

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी करते हुए कहा, 'अमेरिका की अत्यधिक मांगों ने NPT को फ्री फॉल की स्थिति में पहुंचा दिया है. अमेरिका और उसके सहयोगियों की बाधा डालने वाली नीति के कारण NPT समीक्षा सम्मेलन लगातार तीसरी बार असफल रहा.' ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि परमाणु निरस्त्रीकरण नहीं हुआ, तो NPT का भविष्य खतरे में पड़ सकता है. परमाणु अप्रसार संधि (NPT) की समीक्षा बैठक 27 अप्रैल को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शुरू हुई थी. यह सम्मेलन शुक्रवार को अपने अंतिम दिन में पहुंचा, लेकिन सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी. जापान के सार्वजनिक प्रसारक NHK की रिपोर्ट के अनुसार अंतिम दस्तावेज का मसौदा चार बार बदला गया, लेकिन विवादित मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई.

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर टकराव

रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा विवाद उस लाइन को लेकर था जिसमें कहा गया था कि 'ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता, न विकसित कर सकता है और न ही उसकी तलाश कर सकता है.' ईरान ने इस वाक्य को हटाने की मांग की, जबकि अमेरिका इसे अंतिम दस्तावेज में बनाए रखने पर अड़ा रहा. इसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे लंबी बातचीत चली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका. अंतिम दस्तावेज के मसौदे से यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण से जुड़े कई विवादित शब्द भी हटाए गए थे, ताकि सहमति बन सके. इसके बावजूद सदस्य देश अंतिम दस्तावेज पर एकमत नहीं हो पाए. सम्मेलन के अध्यक्ष डो हंग वियेत ने कहा कि सहमति न बन पाना 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' है. NPT समीक्षा सम्मेलन आम तौर पर हर पांच साल में आयोजित किया जाता है. लेकिन यह लगातार तीसरी बार है जब सदस्य देश किसी अंतिम संयुक्त दस्तावेज को स्वीकार करने में विफल रहे हैं।

अमेरीकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मिले पीएम मोदी

नई दिल्ली। भारत के चार दिवसीय यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार (23 मई, 2026) को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उन्होंने पीएम मोदी के साथ मुलाकात को लेकर कहा कि हमने बातचीत में भारत और अमेरिका के संबंधों के महत्व पर जोर दिया. इसके अलावा, मध्य पूर्व की स्थिति, ऊर्जा क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की. पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए एक पोस्ट में कहा, 'मैंने नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत-अमेरिका के संबंधों के महत्व पर जोर दिया. हमने मिडिल ईस्ट की स्थिति, ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका-भारत साझेदारी, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और तकनीकियों में सहयोग पर चर्चा की।

किसके सिर सजेगा IPL 2026 ताज?

राजस्थान का सूखा होगा खत्म या RCB रचेगी इतिहास

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। 4 मैच के बाद इस सीजन की विजेता का फैसला हो जाएगा। रविवार को राजस्थान रॉयल्स की मुंबई इंडियंस पर आसान जीत के साथ ही प्लेऑफ की 4 टीम तय हो गईं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान ने अंतिम-4 में एंट्री ली।

चैंपियन के बीच होगी जंग

आईपीएल 2026 में जिन 4 टीमों ने प्लेऑफ का टिकट कटाया है, उनकी एक खास बात है। सभी टीमों ने लीग के इतिहास में 1-1 ट्रॉफी ही जीती है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चैंपियन टीम प्लेऑफ में पहुंची हों। ऐसे में 31 मई के खेले जाने वाले फाइनल में जो टीम विजेता बनेगी, उसकी यह दूसरी ट्रॉफी होगी। राजस्थान रॉयल्स के पास जहां सालों का सूखा खत्म करने का मौका है तो वहीं आरसीबी इतिहास रच सकती है।

2008 में जीता था खिताब

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के पहले सीजन यानी 2008 में खिताब जीता था। शेन वॉर्न की कप्तानी वाली राजस्थान ने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से शिकस्त दी थी। ऐसे में रियान पराग के पास अब ट्रॉफी का सूखा खत्म करने का अच्छा मौका है। पहले 17 सीजन तक खिताब के लिए तरसने के बाद आरसीबी ने आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। ऐसे में रजत पाटीदार के पास अब खिताब का बचाव करने का मौका है। आईपीएल इतिहास में 2 टीम ही बैक टू बैक चैंपियन बनी हैं। इनमें चेन्नई सुपर किंग्स (2010, 2011) और मुंबई इंडियंस (2019, 2020) शामिल हैं। अगर ऐसा होता है तो रजत पाटीदार भी धोनी और रोहित के स्पेशल क्लब में शामिल हो जाएंगे।

कमिंस के पास जीतने का मौका

सनराइजर्स हैदराबाद 2016 में डेविड वॉर्नर की कप्तानी में आईपीएल विनर बनी थी। इसके बाद कोई भी विदेशी कप्तान आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीता। ऐसे में अब एक और ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस के पास ट्रॉफी कब्जाने का मौका है।

गुजरात की नजर दूसरी ट्रॉफी पर

2022 में आईपीएल में 2 नई टीम जुड़ीं। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने डेब्यू सीजन में ही खिताब जीत लिया। अब शुभमन गिल के पास दूसरी ट्रॉफी अपने नाम करने का मौका है।

प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल

26 मई: क्वालिफायर-1, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस

27 मई: एलिमिनेट, सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स

29 मई: क्वालिफायर-2 (क्वालिफायर-1 हारने वाली बनाम एलिमिनेटर जीतने वाली टीम)

31 मई: फाइनल (क्वालिफायर-1 बनाम क्वालिफायर-2 की विनर टीम)

प्लेऑफ की 4 टीमों का प्रदर्शन

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: 18 प्वाइंट (+0.783)

गुजरात टाइटंस: 18 प्वाइंट (+0.695)

सनराइजर्स हैदराबाद: 18 प्वाइंट (+0.524)

राजस्थान रॉयल्स: 16 प्वाइंट (+0.189)

इन कारणों के चलते चेन्नई नहीं कर सकी प्लेऑफ में प्रवेश

एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेऑफ में पहुंचने का सपना पूरा नहीं हुआ. लगातार दूसरी बार टीम क्वालीफाई करने से चूक गई. आईपीएल 2026 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किसी भयावह सपने से कम नहीं गुजरा. इस सीजन चेन्नई सिर्फ छह मुकाबले ही जीत सकी. यहां जानिए आखिर वो कौनसे कारण रहे, जिसकी वजह से पांच बार की चैंपियन अंतिम चार में जगह नहीं बना सकी.

खिलाड़ियों की इंजरी

चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेऑफ में नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण खिलाड़ियों की इंजरी रहा. नाथन एलिस चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो अच्छी लय में दिखाई दिए आयुष म्हात्रे का इंजरी की वजह से बाहर होना बड़ा झटका रहा. खलील अहमद भी 5 मैच खेलने के बाद चोटिल हो गए जबकि बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दे रहे जेमी ओवरटन भी अहम समय पर इंजरी के कारण आईपीएल 2026 से बाहर हुए.

युवा खिलाड़ियों ने किया निराश

आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने कई युवा खिलाड़ियों पर बड़ा दांव खेला था. प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14-14 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च कर खरीदा था. हालांकि, दोनों खिलाड़ी इस सीजन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके. उर्विल पटेल सिर्फ एक ही अर्धशतक लगा सके.

कप्तान लगातार रहे फ्लॉप

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ लगातार बल्लेबाज से फ्लॉप होते रहे. गायकवाड़ टीम के सबसे मुख्य बल्लेबाज थे, लेकिन उन्होंने हर बार निराश किया. गायकवाड़ आईपीएल 2026 में सिर्फ 123 के स्ट्राइक रेट से 337 रन ही बना सकी.

फिनिशर नहीं उतरे खरे

डेवाल्ड ब्रेविस से आईपीएल 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद थी. हालांकि, ब्रेविस टीम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. ब्रेविस ने 11 मुकाबलों में महज 127 के स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए. ब्रेविस आईपीएल 2026 में एक अर्धशतक तक नहीं लगा सके. वहीं, शिवम दुबे भी इस बार फिनिशर की भूमिका पर खरे नहीं उतरे.

केरल, पंजाब के बाद बिहार में बढ़े दूध के दाम

नई दिल्ली। देशभर में महंगाई का दौर चल रहा है, पेट्रोल-डीजल के बाद अब अन्य रोजमर्रा की चीजों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं. इसी कड़ी में कुछ दिन पहले ही अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियों ने दूध के दाम बढ़ाए थे. जिसके बाद पंजाब और केरल राज्य की कंपनियों ने दामों में बढ़ोतरी की है. अब हाल ही में बिहार की कंपनी सुधा डेयरी ने भी दूध के दामों को बढ़ाने का फैसला कर लिया है. दरअसल बिहार की सुधा डेयरी कंपनी ने दूध के दामों को 2 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है. ये नई कीमतें 22 मई 2026 यानी कल से लागू हो जाएंगी. ऐसे में अब बिहार की आम जनता पर इसका काफी बोझ पड़ने वाला है. सुधा कंपनी के दूध में 2 रुपये की बढ़ोतरी के बाद अब कौन सा दूध कितने रुपये का मिलेगा।

कहीं ₹ 300, तो कहीं ₹190 बढ़ी कीमत दुनिया में पेट्रोल-डीजल के लिए त्राहिमाम

नई दिल्ली। भारत में बीते 10 दिनों में 3 बार पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं. इसके चलते पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कुल लगभग 4.80 प्रति लीटर से लेकर 5.00 रुपये तक का इजाफा हुआ है. रेट बढ़ने के बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. फ्यूल स्टेशनों में भीड़ जमा होने लगी, विरोधी पार्टियां सरकार को बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर घेरने लगी, कहीं-कहीं लोग भी सरकार को कोसने लगे. लेकिन क्या आपको पता है कि इस वक्त इकलौता भारत ऐसा देश है, जहां स्थिति काबू में है. पूरी दुनिया के मुकाबले अकेले भारत में अब तक पेट्रोल-डीजल की कीमतें सबसे कम बढ़ी हैं. दुनिया के बाकी देशों का हाल जानेंगे, तो आपके होश उड़ जाएंगे.

भारत में 3 बार बढ़ी कीमतें

फरवरी से मई 2026 के बीच वैश्विक संकट के बीच अलग-अलग देशों में पेट्रोल में की कीमतों में बंपर उछाल आया है, जिनमें भारत में हुआ इजाफा सबसे कम है. पश्चिम एशिया में सकंट के दबाव में भारत में लंबे समय बाद 15 मई को पेट्रोल-डीजल की कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गईं. इसके ठीक चार दिन बाद 19 मई को दूसरी किश्त में औसतन 90 पैसे प्रति लीटर दाम और बढ़ाए गए. फिर 23 मई को पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे का और इजाफा किया गया. अगर इसकी तुलना दुनिया के दूसरे देशों से किया जाए, तो यह काफी कम है.

सोशल मीडिया पर सचिन ने की अर्जुन की तारीफ

नई दिल्ली। अर्जुन तेंदुलकर पंजाब किंग्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के सबसे किफायती गेंदबाज रहे, जिन्हें इस सीजन पहला मैच खेलने को मिला था. . लीग स्टेज में अपने आखिरी मैच में टीम ने उन्हें मौका दिया, जिसमें उन्होंने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया. मैच के बाद उनके पिता और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उनके लिए एक मैसेज लिखा सचिन ने लिखा, "बहुत बढ़िया, अर्जुन. इस पूरे संस्करण में जिस तरह से तुमने खुद को संभाला है, हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखा, सब्र बनाए रखा, कड़ी मेहनत की, और आखिरी मैच तक अपने मौके का इंतजार करने के बावजूद पॉजिटिव बने रहे, उस पर मुझे बहुत गर्व है." सचिन ने आगे लिखा, "क्रिकेट जितनी तुम्हारी काबिलियत की परीक्षा लेता है, उतनी ही तुम्हारे सब्र की भी और आज तुमने इन दोनों को ही बहुत खूबसूरती से संभाला. हमेशा जमीन से जुड़े रहना, और इस खेल से वैसे ही प्यार करते रहना जैसे तुम हमेशा से करते आए हो."

रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्णवाणी ने बढ़ाई टेंशन

सोना 3 लाख, चांदी होगा 5 लाख के पार

नई दिल्ली। 'Rich Dad Poor Dad' के मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने एक बार फिर से वैश्विक बाजार में ऐतिहासिक गिरावट आने की चेतावनी दी है. साथ ही उन्होंने सोने-चांदी की कीमतों में बंपर उछाल आने का भी अनुमान लगाया है. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में रॉबर्ट कियोसाकी ने दिग्गज मार्केट एनालिस्ट जिम रिकॉर्ड्स के हवाले से कहा है कि आने वाले समय में सोना 100000 डॉलर प्रति आउंस तक पहुंच सकता है. साथ ही चांदी भी 200 डॉलर प्रति आउंस के ऑल टाइम हाई लेवल को टच कर सकती है.

रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पोस्ट में कहा, "मार्केट में गिरावट तय है. जिम रिकार्ड्स का अनुमान है कि सोना 100,000 डॉलर तक पहुंच जाएगा. आज सोने की कीमत 4,500 डॉलर है. मुझे लगता है कि चांदी की कीमत 200 डॉलर प्रति आउंस तक पहुंच जाएगी. आज चांदी की कीमत 75 डॉलर है." रॉबर्ट कियोसाकी का यह बयान एक ऐसे वक्त पर आया है, जब वैश्विक बाजार पहले से ही बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, लगातार बनी हुई महंगाई, बढ़ते सरकारी कर्ज और केंद्रीय बैंक की नीतियों को लेकर बनी अनिश्चितता से जूझ रहा है.

आखिर किस ओर बढ़ रही है दुनिया?

कियोसाकी की इस ताजा चेतावनी ने एक बार फिर इस बात पर चर्चा छेड़ दी है कि क्या दुनिया एक और बड़े वित्तीय बदलाव (financial reset) की ओर बढ़ रही है, जो आखिरकार निवेशकों को ठोस संपत्तियों (hard assets) की ओर धकेल सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, "सबसे अच्छे निवेशक वे होते हैं जो भविष्य को देख पाते हैं और उसके अनुसार कदम उठाते हैं. याद रखें, इस गिरावट (crash) में आपको पीड़ित बनने की जरूरत नहीं है. आप और भी अमीर बन सकते हैं." सालों से, कियोसाकी लगातार इस बात की वकालत करते रहे हैं कि सिर्फ कागजी मुद्राओं या पारंपरिक वित्तीय संपत्तियों पर निर्भर रहने के बजाय, सोना, चांदी और बिटकॉइन जैसी असली संपत्तियों को अपने पास रखना चाहिए. उनकी ताजा टिप्पणियां एक बार फिर उनके इस पुराने विचार को मजबूती देती हैं. उन्होंने बिटकॉइन के भी 750,000 डॉलर तक पहुंचने की बात कही है. बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और देशों पर बढ़ते सरकारी कर्ज को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स आंशिक रूप से सहमत हैं कि सोने-चांदी की कीमतों में आने वाले समय में तेजी बनी रहेगी. हालांकि, कई कियोसाकी की आलोचना भी करते हैं कि वे सालों से बाजार क्रैश होने की एक जैसी भविष्यवाणियां करते आ रहे हैं।

काव्या मारन ने क्रुणाल पांड्या की गेंदबाजी पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी की मालकिन काव्या मारन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या की गेंदबाजी एक्शन पर सवाल खड़े किए. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस मैच में SRH ने RCB को 55 रनों से हरा दिया. हालांकि जीत के बावजूद हैदराबाद टॉप-2 में नहीं पहुंच पाई. शुक्रवार को हुए इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. क्रुणाल पांड्या ने इस मैच में सिर्फ 2 ही ओवर डाले, जिसमें उन्होंने 12 की इकॉनमी से 24 रन लुटाए और 1 विकेट लिया. काव्या मारन ने क्रुणाल के एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं।

"किसे क्या बनाना है, यह दिल्ली तय करेगी, मैं बुद्धि नहीं लगाता"

टीएस सिंहदेव के बयान पर भूपेश बघेल का दो टूक जवाब

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 'संगठन की कमान' को लेकर एक बार फिर शह और मात का खेल शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की कुर्सी को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहद कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के हालिया बयानों पर सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से बचते हुए बघेल ने साफ कर दिया कि पार्टी में पदों का फैसला सिर्फ और सिर्फ 'दिल्ली दरबार' (हाईकमान) करता है।राजीव भवन में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान भूपेश बघेल ने न केवल अपनी ही पार्टी के भीतर चल रही लॉबिंग को शांत करने की कोशिश की, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला।

बैज का बचाव, सिंहदेव के बयान से किनारा

पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर मचे अंदरूनी घमासान पर भूपेश बघेल ने वर्तमान अध्यक्ष दीपक बैज का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा दीपक बैज पिछले तीन-साढ़े तीन साल से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में एकजुट होकर काम कर रही है। किसे नेता प्रतिपक्ष बनाना है और किसे प्रदेश अध्यक्ष, यह तय करना हाईकमान का काम है। "मैं इन सब चीजों में अपनी बुद्धि नहीं लगाता।"

"4 दिन में 2 करोड़ फॉलोअर्स..." अब 'Gen-Z' के भरोसे कांग्रेस!

भूपेश बघेल ने युवाओं (Gen-Z) की ताकत को रेखांकित करते हुए देश के बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर एक बेहद दिलचस्प उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आजकल 'Gen-Z' का जमाना है, जिसका अद्भुत प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिला है कि कैसे महज 4 दिन में 2 करोड़ फॉलोअर्स मिल जाते हैं। राहुल गांधी खुद इस नई पीढ़ी को आमंत्रित कर रहे हैं। युवा कांग्रेस के आगामी चुनावों में 90 के दशक के बाद पैदा हुए लड़के संगठन का नेतृत्व संभालेंगे। देश में आज लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लेकिन यह नई पीढ़ी इसे दोबारा खड़ा करने की इच्छाशक्ति रखती हैप्रेसवार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए देश के हालातों की तुलना 'अघोषित आपातकाल' से कर दी। देश में मीडिया को चुप करा दिया गया है और उद्योग जगत को डराकर मौन रखा गया है। हम बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे हम अमेरिका के कुचक्र में फंस चुके हैं। हमें क्रूड ऑयल (तेल) के लिए लगातार दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आम जनता त्रस्त है क्योंकि हाल ही में डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के दामों में ₹5 तक की भारी बढ़ोतरी हुई है।

बिजली कटौती को लेकर भाजपा नेताओं के घर जाएगी कांग्रेस

रायपुर। रायपुर में लगातार बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस CSPDCL के दफ्तर पहुंची। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं ने CSPDCL के अधिकारी संजीव सिंह और शहर के सभी जोन के मुख्य कार्यपालिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने कहा कि आम लोग परेशान हैं, अगर बिजली कटौती की समस्या दूर नहीं होती है तो हम भाजपा के सांसद, विधायक और पदाधिकारियों के घर जाकर धरना देंगे। कांग्रेस नेताओं ने बैठक में शहर के अलग-अलग इलाकों में हो रही बार-बार बिजली कटौती, लो-वोल्टेज और खराब बिजली व्यवस्था का मुद्दा उठाया। नेताओं ने कहा कि गर्मी के मौसम में लगातार बिजली गुल होने से आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इससे पहले बिजली कटौती से परेशान लोगों को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय डगनिया बिजली ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए थे। डगनिया और आसपास के इलाकों के लोग भी बड़ी संख्या में धरने में शामिल हुए थे। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियमित बिजली सप्लाई की मांग की थी।

पीसीसी चीफ बोले, गृहमंत्री बदलने के बजाय सिस्टम बदली करने में लगी है सरकार

राजधानी के बाद अन्य शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया जाना फिजूल खर्ची

शहर सत्ता/रायपुर। राजधानी के बाद अन्य शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया जाना फिजूल खर्जी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम फेल हो गया, अब दुर्ग बिलासपुर में लागू करेंगे। अपराधों में नियंत्रण का नाम लेकर रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गयी, 5 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गयी। उसके बाद भी अपराधों में कोई नियंत्रण नहीं हुआ। आज भी लूट, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक के साथ लूट हो जाती है। इस फेल सिस्टम को भाजपा सरकार दुर्ग, बिलासपुर में भी लागू करने जा रही है। सरकार बताये कि रायपुर में लागू करने का क्या फायदा हुआ? प्रदेश में बढ़ते अपराध के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार है। गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। बीमारी कुछ है, इलाज कही और ढूंढा जा रहा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि रायपुर पुलिस कमिश्नरी वसूली कमिश्नरेट बन गया है। राजधानी की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था को सुधारने के नाम पर सरकार ने राजधानी में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया था, राजधानी की कानून व्यवस्था में कोई सुधार तो नहीं हुआ। कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के कारण नागरिकों की परेशानी जरूर बढ़ गई। अपराध और अपराधी तो बेलगाम है ही अब सड़क पर पुलिस का चालान नागरिकों में एक नया खौफ पैदा कर रहा है। कमिश्नरी प्रणाली का काम केवल ट्रैफिक के नाम पर वसूली करना मात्र ही है। क्या पुलिस अपराधों के नियंत्रण तथा पुलिस की गश्ती व्यवस्था को सुधारने गली, मुहल्ले में पुलिस के संरक्षण में बिक रहे सूखे नशे के कारोबार पर भी रोक लगाना भी है, पुलिस की पूरी सक्रियता केवल चालान भेजने और वसूली करने तक है? किसी चौराहे पर लोगों की मदद करते पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी कभी नहीं दिखता है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। लूट, हत्या, बलात्कार, चाकूबाजी की घटनाओं के कारण पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा अकेला राज्य है, जहां पर कलेक्टर, एसपी कार्यालय जला दिया गया, अपराधी को गांव वालो ने उसके घर में जिंदा जला दिया, एसडीएम को जनता मारने दौड़ा दिया उसे जान बचाकर भगाना पड़ा।

स्मार्ट मीटर आम आदमी के गले का फांस बन गया है : कांग्रेस

शहर सत्ता/रायपुर। स्मार्ट मीटर आम आदमी के गले का फास बन गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हर जगह बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उनकी खपत वास्तविक खपत से अधिक बताई जा रही है, स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर की तुलना में बहुत तेजी से चल रहा है। बिजली उपभोक्ताओं का यह अधिकार है कि अपनी वास्तविक खपत को जान सके। चेक मीटर का प्रावधान पहले से ही था, लेकिन यह सरकार अपनी लूट पर परदेदारी करने के लिए चेक मीटर लगाने और मीटर चेक करवाने उपभोक्ताओं से 1000 और 1500 रुपए शुल्क लेने का प्रावधान कर दिया गया है, यदि मीटर में गड़बड़ी का आरोप उपभोक्ता लगा रहे हैं, तो उसे मुफ्त में चेक किया जाए, किसी भी तरह से अतिरिक्त शुल्क अनुचित है। यह प्रावधान सरकार ने गड़बड़ी छुपाने के लिये किया है। सरकार स्मार्ट मीटर वापस ले। स्मार्ट मीटर वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि स्मार्ट मीटर के कारण बिजली की खपत से ज्यादा रीडिंग आ रही है। जनता परेशान है। इस माह लोगों का बिल तीन गुना तक बढ़कर आया है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूरे प्रदेश से स्मार्ट मीटर वापस लिया है। हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ से भी स्मार्ट मीटर वापस लिया जाये। उत्तरप्रदेश सरकार ने माना कि स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत ज्यादा आ रही है, योगी मंत्रिमंडल ने इसे बदलने का फैसला किया है, छत्तीसगढ़ में भी इसे वापस लिया जाए।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार ने बिजली के दाम चार बार बढ़ा दिया। 400 यूनिट हाफ योजना को बंद कर दिया। स्मार्ट मीटर लगा दिया इन सबसे बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ गए, जनता परेशान है। सरकार, जनता को राहत देने के बजाय अब बिजली के दामों में 12 प्रतिशत विद्युत ईंधन अधिभार (एफपीपीएस) के रूप में अतिरिक्त चार्ज इस महीने से लगाने जा रही, इससे बिजली के दाम एक बार फिर से बढ़ेंगे।

29 मई से नामांकन शुरू; पिछली कमेटियां तत्काल प्रभाव से भंग, 'एक व्यक्ति-एक पद' के कड़े नियम लागू

8 सेकंड का वीडियो' और 'वोटर ID तय करेगी युवा कांग्रेस का भविष्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस अब पूरी तरह से नए और हाइटेक रंग में नजर आने वाली है। प्रदेश में संगठनात्मक चुनावों का बिगुल फूंक दिया गया है, लेकिन इस बार का मुकाबला पारंपरिक नहीं बल्कि पूरी तरह 'डिजिटल' होने जा रहा है। फर्जी सदस्यता और चुनावी धांधली को रोकने के लिए आलाकमान ने इस बार सख्त और अभेद्य नियम तैयार किए हैं।राजीव भवन में भारतीय युवा कांग्रेस के मुख्य चुनाव आयुक्त जसप्रीत सिंह और प्रदेश चुनाव अधिकारी रोशन नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आचार संहिता लागू होने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ राज्य की वर्तमान कमेटियां भंग हो गई हैं।

चुनावी टाइमलाइन: कब क्या होगा?

पारदर्शी और समयबद्ध चुनाव कराने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ को 5 जोन में बांटकर जोन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर्स (ZRO) तैनात। चुनावी शेड्यूल कुछ इस तरह है:

ब्लॉक और जिला कमेटी नामांकन	29 मई से 13 जून
प्रदेश अध्यक्ष व कार्यकारिणी नामांकन	11 जून से 13 जून
नामांकनों की स्क्रूटनी (जांच)	15 जून से 18 जून
सदस्यता अभियान व ऑनलाइन वोटिंग	स्क्रूटनी के तुरंत बाद एक साथ

'हाई-टेक सुरक्षा'

युवा कांग्रेस में अक्सर होने वाली 'फर्जी और थोक सदस्यता' की शिकायतों को खत्म करने के लिए इस बार तकनीक का कड़ा पहरा रहेगा:

लाइव वीडियो वेरिफिकेशन: सदस्य बनने के इच्छुक युवा को आवेदन के साथ अपना 8 सेकंड का एक लाइव वीडियो अपलोड करना होगा। इसमें आवेदक को खुद बताना होगा कि वह सदस्यता क्यों ले रहा है।

वोटर ID के बिना नो एंट्री: फर्जीवाड़े रोकने के लिए वोटर आईडी कार्ड को अनिवार्य पहचान पत्र बना दिया गया है।

उम्र का कड़ा दायरा: चुनाव लड़ने और सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है। उम्र की पुष्टि के लिए 10वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज ही मान्य होंगे।

'वन मैन, वन पोस्ट'

पार्टी ने साफ कर दिया है कि संगठन में रसूखदारों का एकाधिकार नहीं चलेगा। कोई भी दावेदार सिर्फ एक ही पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। यदि कोई पदाधिकारी नए पद के लिए पर्चा भरता है, तो नामांकन दाखिल करते ही वह अपने पुराने पद से मुक्त मान लिया जाएगा।

करही बाजार में सुशासन तिहार

मुख्यमंत्री ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों व होनहार विद्यार्थियों को दी लाखों की सौगात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार के करही बाजार में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम में तेन्दूपत्ता संग्राहकों और शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की। ग्रामीणों, संग्राहकों और विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल रहा, और अनेक लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। वर्ष 2025-26 के भुगतान के तहत तेन्दूपत्ता संग्राहकों को भुगतान किया गया। धनेली समिति के रामपुर फड़ की श्रीमती कमला बाई को 3510 गड्डियों के एवज में 19,305 रुपये तथा केसला फड़ की श्रीमती कांती बाई को 5,000 गड्डियों के लिए 27,500 रुपये प्रदान किए गए। वहीं वर्ष 2026-27 के लिए भी लाभार्थियों को भुगतान जारी रखा गया। धनेली समिति के रामपुर फड़ के श्री कौसल साहू को 3,310 गड्डियों के अनुसार 18,205 रुपये दिए गए।

शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत मेधावी तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी आर्थिक प्रोत्साहन दिया गया। वर्ष 2023-24 में मोपका फड़ की तपेश्वरी साहू को प्रतिभाशाली योजना के तहत 15,000 रुपये, तारनी को 25,000 रुपये तथा रामपुर फड़ की चांदनी साहू को मेधावी योजना में 3,000 रुपये दिए गए। वर्ष 2024-25 के भुगतान (21 मई 2026 को) में बिटकुली फड़ के सागर देवांगन को प्रतिभाशाली योजना में 25,000 रुपये, गुडा फड़ की कृतिका देवा को 15,000 रुपये तथा चिचपोल फड़ के खिंदु को मेधावी योजना के तहत 25,000 रुपये प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वनवासियों, श्रमिकों और विद्यार्थियों के जीवन स्तर को सुधारने और उनकी आर्थिक-शैक्षिक स्थिति मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जबकि बड़ी संख्या में ग्रामीणजन भी उपस्थित होकर इस पहल का समर्थन कर रहे थे। लाभार्थियों ने शासन की योजनाओं से मिली आर्थिक सहायता और बच्चों की पढ़ाई के अवसरों के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि यह मदद उन्हें आत्मनिर्भर बनने और शिक्षा को आगे बढ़ाने की नई प्रेरणा देगी।

समाधान शिविर में किया ताबड़तोड़ निराकरण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत बलौदाबाजार जिले के करहीबाजार में आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने आम जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं, विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए तथा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और गांव-गांव जाकर समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार यह जानने के लिए गांवों तक पहुंच रही है कि लोगों को पानी, बिजली, सड़क, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाएं समय पर मिल रही हैं या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार बनते ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए तथा अब तक 26 लाख आवास स्वीकृत हो चुके हैं। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और दो वर्षों का बकाया बोनस भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, घरेलू जरूरतों और छोटे व्यवसायों के लिए कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।

सुदर्शन सिंह को मिला जमीन का कानूनी अधिकार

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित सुशासन तिहार 2026 आमजन की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। स्वामित्व योजना के जरिए ग्रामीण परिवारों को वर्षों पुरानी जमीन का वैधानिक अधिकार मिल रहा है, जिससे उनमें सुरक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान की भावना मजबूत हो रही है। मरवाही विकासखंड की ग्राम पंचायत उषाड़ में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में ग्राम कछार निवासी श्री सुदर्शन सिंह को अधिकार अभिलेख पत्र प्रदान किया गया। अधिकार अभिलेख मिलते ही उनके चेहरे पर खुशी और संतोष झलक उठा। उन्होंने शासन, राजस्व विभाग एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें अपनी जमीन का कानूनी मालिकाना हक मिल गया है। श्री सुदर्शन सिंह ने बताया कि उनका परिवार वर्षों से जिस भूमि पर निवास कर रहा था, उसके वैधानिक दस्तावेज न होने से हमेशा असुरक्षा की भावना रहती थी। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, बैंक संबंधी कार्यों और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में कठिनाई होती थी। स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेख मिलने के बाद अब उनका परिवार निश्चिंत और आत्मविश्वास से भरा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित समाधान कर रही है। सुशासन तिहार के माध्यम से गांव-गांव तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और आम लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण हो रहा है। इससे ग्रामीणों का शासन और प्रशासन के प्रति विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है।

चलने में असमर्थ बुजुर्गों के द्वार पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, घर बैठे बन रहे आयुष्मान वय वंदन कार्ड

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान (बस्तर मुन्ने) एवं सुशासन तिहार के अंतर्गत सुकमा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक सुलभ कराने के लिए एक बेहद संवेदनशील पहल की जा रही है। इसी कड़ी में दोरनापाल शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम ने 70 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे बुजुर्गों के घर पहुंचकर आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाए, जो शारीरिक अस्वस्थता के कारण चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ हैं। शासन की मंशा है कि कोई भी पात्र और जरूरतमंद बुजुर्ग इस जनकल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे, इसीलिए स्वास्थ्य अमला स्वयं घर-घर दस्तक दे रहा है। दोरनापाल निवासी वयोवृद्ध श्री आत्माराम साहू का भी उनके निवास पर पहुंचकर कार्ड तैयार किया गया। प्रशासन की इस संवेदनशीलता को देखकर वे भावुक हो उठे और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शासन-प्रशासन के इस प्रयास से अब उन्हें वृद्धावस्था में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कोई आर्थिक चिंता नहीं सताएगी। उल्लेखनीय है कि आयुष्मान वय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा और कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। यह योजना समाज के बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक स्वास्थ्य सुरक्षा देने की दिशा में राज्य सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। सुकमा जिले में जिला प्रशासन की यह अनूठी मुहिम सुशासन तिहार के मूल उद्देश्यों को धरातल पर साकार कर रही है।

एर्राबोर के सुशासन शिविर में 5 लखपति दीदियों का सम्मान

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और सुकमा कलेक्टर श्री अमित कुमार के मार्गदर्शन में संचालित सुशासन तिहार एवं बस्तर मुन्ने अभियान अब दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में भी बदलाव की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोंटा विकासखंड के एर्राबोर में आयोजित क्लस्टर स्तरीय सुशासन शिविर में 10 पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण उत्साहपूर्वक शामिल हुए। शिविर में प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान करते हुए विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया। इससे ग्रामीणों में शासन के प्रति विश्वास और उत्साह देखने को मिला। शिविर का विशेष आकर्षण क्षेत्र की 5 महिलाओं को "लखपति दीदी" प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करना रहा। सोयम समशाद, सोढ़ी गंगी, बोड्डी मीना, रवा सुक्की और सेमला बजारी को आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सोयम समशाद को स्वयं का व्यवसाय बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण चेक भी प्रदान किया गया।

452 आवेदनों का मौके पर निराकरण : सुशासन शिविर में विभिन्न विभागों को कुल 452 आवेदन प्राप्त हुए। राजस्व, स्वास्थ्य, पंचायत और अन्य विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जॉब कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसे दस्तावेजों का त्वरित निराकरण किया। ग्रामीणों को शिविर स्थल पर ही आभा आईडी और स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

'एलियन' बन बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएंगे अक्षय

हॉलीवुड की टीम डिजाइन करेगी लुक और एक्शन सीक्वेंस

भूत बंगला की कामयाबी के बाद अब अक्षय कुमार एक और थ्रिलर फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने की तैयारी में हैं। खिलाड़ी कुमार की नई फिल्म आ रही है जो एलियन एक्शन थ्रिलर समुक (Samuk) है। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म समुक भारत की पहली बड़े स्तर की एलियन थ्रिलर बताई जा रही है। फिल्म का निर्देशन 'सनक', 'इनसाइड एज' और 'ग्लोरी' जैसे प्रोजेक्ट्स बना चुके कनिष्क वर्मा (Kanishk Varma) करने वाले हैं जबकि फिल्म का निर्माण विपुल अमृतलाल शाह (Vipul Amrutlal Shah) कर रहे हैं।

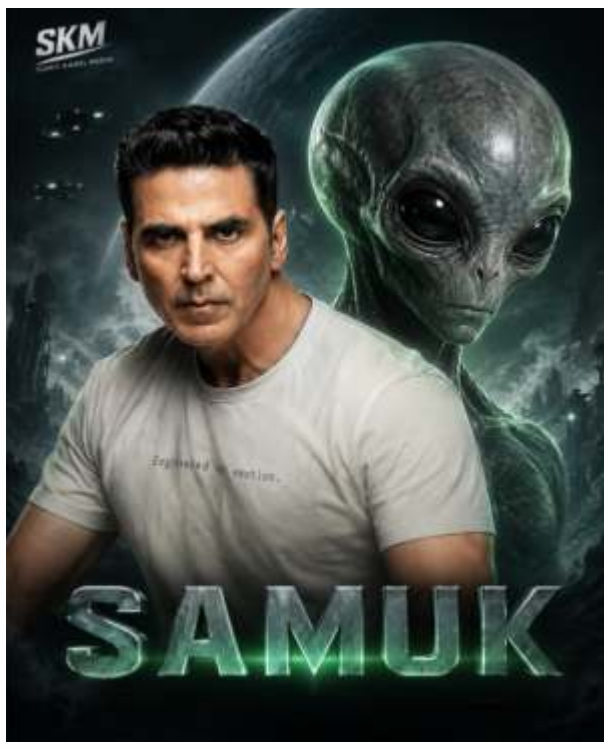

अक्षय की नई फिल्म का ऐलान

अक्षय कुमार ने समुक का हिस्सा बनने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, "हां मैंने यह फिल्म साइन की है। समुक की कहानी और विषय मुझे बेहद दिलचस्प लगे। एलियन थ्रिलर मेरे लिए और हमारी फिल्मों के लिए बिल्कुल नया जॉनर है। मैं इसे लेकर काफी उत्साहित हूं।"

एलियन बनेंगे अक्षय कुमार

वहीं, निर्देशक कनिष्क ने फिल्म को लेकर बताया, "समुक मेरे एसपीजी वर्ल्ड और एलियन व प्रिडेटर जैसी सर्वाइवल थ्रिलर्स के प्रति प्यार से पैदा हुई है। अक्षय सर के साथ इन सभी चीजों को एक साथ लाना बेहद खास अनुभव रहा है। मैं हमेशा चाहता था कि फिल्म का एलियन सेट पर वास्तविक महसूस हो। वही पुराना टैक्टाइल हॉरर फिल्मों को यादगार बनाता है।"

हॉलीवुड का मिला साथ

अक्षय कुमार की इस फिल्म के साथ हॉलीवुड की बड़ी टेक्निकल टीम भी जुड़ी है। मशहूर क्रिएचर एफएक्स डिजाइनर एलेक गिलिस (Alec Gillis) फिल्म के एलियन क्रिएचर को डिजाइन और तैयार करेंगे। एलेक गिलिस 'एलियन', 'प्रिडेटर', 'एलियन: रोमुलस', 'स्टारशिप ट्रूपर्स', 'स्माइल', 'इट' और 'ट्रेमर्स' जैसी फिल्मों पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वहीं एक्शन सीक्वेंस ब्रिटिश स्टंट कोऑर्डिनेटर ल्यूक टंबर (Luke Tumber) डिजाइन करेंगे। यह फिल्म 2027 में बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है।

डेविड धवन के रिटायरमेंट पर इमोशनल हुए करण

निर्देशक डेविड धवन इन दिनों अपनी आखिरी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं. कल ही फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ हैं, जिसके ट्रेलर लॉन्च में कई सेलेब्स के साथ करण जोहर भी पहुंचे थे. इसी बीच करण ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल स्टोरी शेयर कर डेविड धवन की तारीफ की हैं और उनकी आखिरी फिल्म को शुभकामनाएं दी. करण जौहर ने अपने स्टोरी में लिखा, 'कल जब मैं डेविड जी के सेलिब्रेशन में गया और उन्होंने मुझे बताया कि ये उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है, तो मेरे दिल में एक साथ खुशी और दुख दोनों तरह की इमोशंस आईं. वो ऐसे फिल्ममेकर हैं, जिन्होंने फिल्मों की एक पूरी अलग शैली बनाई है. डेविड धवन की फिल्म का मतलब ही भरपूर एंटरटेनमेंट होता है. सोचिए, जब ऐसा इंसान ये कहता है कि अब वो अपनी आखिरी फिल्म बना रहे हैं, तो उन्हें अंदर से कैसा महसूस होता होगा.' उन्होंने आगे लिखा, 'वो खुद एक ऐसी संस्था हैं, जिनसे ना जाने कितने फिल्ममेकर्स ने प्रेरणा ली है. हमारी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें बेहद प्यार करती है, उनकी इज्जत करती है और उन्हें सेलिब्रेट करती है. इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता. अपने बेटे के साथ आने वाली आपकी इस समर ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. डेविड धवन हमेशा नंबर 1 रहेंगे।

वैजयंतीमाला की दीवानी हुईं कंगना, इंस्टा पर किया पोस्ट

एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में कंगना ने क्लासिकल डांसर वैजयंतीमाला के लिए एक पोस्ट शेयर किया. कंगना ने वैजयंतीमाला का भरतनाट्यम परफॉर्मेंस वाला पुराना वीडियो पोस्ट करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांध दिए.

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वैजयंतीमाला का एक विंटेज वीडियो शेयर किया, जिसमें दिग्गज एक्ट्रेस ट्रैडिशनल अंदाज में क्लासिकल डांस करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो के साथ कंगना ने दिल छू लेने वाला नोट लिखते हुए उनकी कला, खूबसूरती और ग्रेस की जमकर तारीफ की. कंगना ने लिखा, 'बस एक बात याद दिलाना चाहती हूं कि धरती पर रहने वाला हर इंसान आम नहीं होता, कुछ लोग दिव्य होते हैं और सिर्फ हम जैसे लोगों द्वारा पूजे जाने के लिए जन्म लेते हैं.'

बता दें, वैजयंतीमाला का जन्म 13 अगस्त 1933 को हुआ था. उन्होंने महज 16 साल की उम्र में साल 1949 में तमिल फिल्म 'वाझकाई' से एक्टिंग की शुरुआत की थी. इसके बाद 1951 में उन्होंने फिल्म 'बहार' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा. 1954 में आई फिल्म 'नागिन' की सफलता ने उन्हें देशभर में बड़ी पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने 'देवदास', 'मधुमती', 'गंगा जमुना', 'संगम' और 'ज्वेल थीफ' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया. दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में गिनी जाती है.

वैजयंतीमाला का शानदार सफर

सिनेमा के अलावा वैजयंतीमाला ने भरतनाट्यम की दुनिया में भी इंटरनेशनल पहचान हासिल की. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत दुनिया के कई मंचों पर अपनी शानदार प्रेजेंस से भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया. उनके डांस पर लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड हुए कई गाने आज भी याद किए जाते हैं, जिनमें 'होठों पे ऐसी बात' खास तौर पर काफी पॉपुलर रहा. फिल्मों और नृत्य के साथ-साथ वैजयंतीमाला ने राजनीति में भी अहम भूमिका निभाई।

10 दिन में बजट भी वसूल नहीं पाई 'पति पत्नी और वो दो'

नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही है. फिल्म को जब सिनेमाघरों में रिलीज किया गया तो इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला जुला रिएक्शन मिला. आयुष्मान और वामिका की केमिस्ट्री को भी लोगों ने पसंद किया लेकिन ये 'राजा शिवाजी', 'दृश्यम 3' और 'करुप्पू' की आंधी के बीच बजट तक नहीं वसूल पाई. लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड बना दिया है.

50 करोड़ के पार पहुंची कमाई

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'पति पत्नी और वो दो' ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे शनिवार यानी कि 9वें दिन कमाल का बिजनेस किया है. वीकडेज की कमाई के मुकाबले दूसरे शनिवार को इसकी कमाई में 83 प्रतिशत की बंपर उछाल दर्ज की गई है और फिल्म ने ग्लोबली 50 करोड़ के कलेक्शन का आंकड़ा भी पार कर लिया है. 'पति पत्नी और वो दो' की 9वें दिन की कमाई पर नजर डाली जाए तो कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने दूसरे शनिवार 9वें दिन 3.13 करोड़ (इंडिया नेट कलेक्शन) रुपये कमाए. जबकि इसके पहले दूसरे शुक्रवार को इसकी कमाई 1.71 करोड़ दर्ज की गई थी, इस लिहाज से फिल्म 83% का तगड़ा उछाल मिला है. वहीं, फिल्म ने पहले हफ्ते 33.75 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 38.59 करोड़ रहा.

बजट का कितना पर्सेंट वसूल पाई

वहीं, बात की जाए कि फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' बजट का कितना प्रतिशत वसूल पाई है तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 60 करोड़ है. इसका इंडिया नेट कलेक्शन 38.59 करोड़, ओवरसीज कलेक्शन 6.95 करोड़ और वर्ल्डवाइड 52.48 करोड़ महज 9 दिन में कमाए. इस लिहाज से फिल्म बजट का 64.3% वसूल चुकी है.

'कारा' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म

साउथ एक्टर धनुष की फिल्म 'कारा' 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई. वहीं फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां रिलीज होगी? 'कारा' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और ये अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. बता दें कि मेकर्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को फिल्म के राइट्स बेच दिए हैं. ये फिल्म 28 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी. फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर दर्शकों में भी काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है. 'कारा' की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर विग्नेश राजा हैं।

न्याय व्यवस्था में मुड़ा का स्थान

डा. वेदवती मंडावी

आदिवासी अंचल में बाहरी व्यक्तियों अथवा अधिकारियों के आने पर ग्रामवासियों के लिए ग्राम प्रधान प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। ग्रामवासी तथा बाह्य प्रशासन के बीच मध्यस्थता की स्थिति उसकी प्रतिष्ठा के कारण होती है, जिसका वह जब चाहे लाभ उठा सकता है। यह पद वंशानुगत तथा प्रतिष्ठित अथवा विस्तृत गोत्र वालों को दिया जाता है। ग्राम प्रधान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अधिकांश गांव वालों पर अपना प्रभाव रखता है तथा उसके अनुयायी उसे अपना मार्गदर्शक अथवा पारस्परिक मूल्यों का रखवाला समझते हैं। गांव के अधिकांश फैसलों पर उसका व्यक्तिगत प्रभाव होता है। छत्तीसगढ़ में बाइसन हार्न तथा मारिया जनजातियों में इन्हें पेट्टा, अबूझमाड़िया, पटेल, पंडो, कोड़कु, खैरवार, प्रधान एवं नगेसिया जनजाति स्थानीय भाषा में मुखिया कहते हैं कमार जनजाति कुरहा और गोंड मुकद्दम कहते हैं। प्रायः सभी समस्याओं का समाधान आसानी से सुलझाया जाता है। जिन समस्याओं का समाधान कठिन होता है उसे बड़े पंचायत में ले जाते हैं जिसे मुड़ा कहा जाता है। दस पंद्रह पंचायतों को मिलाकर मुड़ा बनाया जाता है। सभी मुखिया मुड़ा के सदस्य होते हैं। मुड़ा के प्रधान को मुड़ादार कहा जाता है।

धरम के जगा आय धमधा

दुर्ग जिला मुख्यालय ले 35 कि मी दूरिहा आज के धमधा कभू धरमदा, धमधागढ़, धर्म गढ़, धरमगढ़ कहाय। धमधागढ़ आजो गोंड मन के तीरथ जगा आय। धमधा नगर के नाव कबीर साहब के शिष्य धरमदास के नाव म रिहिस अपभ्रंश म धमधा होगे। महाकवि तुलसीदास अपन महाकाव्य रामचरित मानस म ये जन्मभूमि के सुंदरता, आनंद अउ सुख के बखान कराय हे -

> राम धामदा पुरी सुहावनि
> लोक समस्त विदित अति पावनि।

एकरे संग तुलसीदास के ए चौपाई अउ रामचरित मानस म आय कतको शब्द जौन धमधा अंचल म बोले जाथे, तेखरे आधार म ए कहे जा सकथे, श्रीराम के धमधा आगमन होय रिहिस। विनय पत्रिका म आय कुछ शब्द घलो ए बात के पुष्टि करथे-

> अतिप्रिय मोहि इहां के वासी
> मम धामदा पुरी सुख रासी।

एकरे संग धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अउ पुरातात्विक महत्व के जगा आय आज के धमधा।

छुईखदान अंचल के प्रमुख जंगल सत्याग्रहियों में गुलाब दास वैष्णव

वीरेंद्र बहादुर सिंह

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गुलाब दास वैष्णव का जन्म सन 1905 में छुईखदान से 12 कि मी दूर सड़क अतरिया में हुआ था। 24 जनवरी 1939 को समारूराम महोबिया के नेतृत्व में चंपाटोला से गंडई तक निकाले गए जंगल सत्याग्रह में वे प्रमुख सत्याग्रही थे। इस आंदोलन के दौरान पुलिस ने वैष्णव सहित 11 सत्याग्रहियों को हिरासत में लिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस के ऐतिहासिक बम्बई अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी के करो या मरो के सन्देश का प्रचार प्रसार करते हुए तथा मुंबई अधिवेशन की बुलेटिन का वितरण करते हुए वे गिरफ्तार किए गए। कारावास की सजा काटने के बाद गुलाब दास ने डोंगरगांव को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। उन्होंने डोंगरगांव में लोक शाला का संचालन प्रारम्भ किया, जहां बच्चों को हस्तशिल्प कला की शिक्षा दी जाती थी। बाद में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नार्मल स्कूल का संचालन शुरू किया, जहां शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। यहीं नार्मल स्कूल बाद में बुनियादी प्रशिक्षण शाला डोंगरगांव के रूप में परिवर्तित हो गया। सन 1973 में आपका निधन हुआ। सड़क अतरिया के हाईस्कूल का उन्नयन जब हायर सेकेण्डरी स्कूल के रूप में हुआ तब उसका नाम श्री वैष्णव के सम्मान में दाऊ गुलाब दास वैष्णव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अतरिया (रोड) रखा गया है।

शिवरीनारायण में मिला रत्नदेव द्वितीय का ताम्रलेख

प्रो. अश्विनी केशरवानी

शिवरीनारायण में मिले ताम्रलेख के प्रथम श्लोक में ब्रम्हा की स्तुति की गई है। इसके बाद चंद्रवंश में कोकल्ल देव तथा उसके अठारह पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। उसके भाई वंकराज को तुम्मान का शासक कहा गया है। वंकराज का पुत्र कलिंगराज और उसके पुत्र कमलराज का उल्लेख है। इसके बाद क्रमशः रत्नराज प्रथम, पृथ्वीदेव, जाजल्यदेव तथा रत्नदेव द्वितीय का वर्णन है। इस ताम्रलेख में कुल 18 श्लोक हैं जो संवत 878 भाद्र शुक्ल पंचमी रविवार का है। इसकी भाषा संस्कृत है। प्रारम्भ में यह ताम्रलेख शिवरीनारायण मंदिर के प्रमुख पुजारी प. रामचंद्र भोगहा महाराज के घर पर था। हर श्लोक कहीं न कहीं मनुष्यों के धर्म कर्म और दान पुण्य के महत्व को स्पष्ट करता है।

आंचलिक लोक कला में रास का रस

डा. उग्रसेन कन्नौजे

विभिन्न विद्वानों के मतानुसार रास की उत्पत्ति रस से हुई है। इसी तरह अनेक विद्वान भगवान कृष्ण की रहस्य के वैभव गाथा से लेते हैं। पद्म पुराण पाताल खंड में रास के लिए रस की प्रधानता मानी गई है। भगवान श्रीकृष्ण भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं नायिका का रूप धारण कर लेते हैं। इस रहस्य को किसी ने जाना नहीं और जो जाना वह उसी का हो गया। भगवान श्रीकृष्ण गोपियों के साथ रास विलास करके भी वे योगी कहलाए, यह एक रहस्य है। इस प्रकार रास शब्द की उत्पत्ति कृष्ण और राधा की रसमय लीला से हुई है जैसा कि महारास में बताया गया है। यह सभी रहस्यों का चित्रण हमारे अंचल के रहस लीला मंच में मंचन किया जाता है। यह बात अलग है कि पूर्व की भांति अब रहस लीला मंचन अनेक कारण से कमी देखी जा रही है।

बस्तर के जंगलों में सेवा-समर्पण की तीन मिसालें पुरस्कृत

- बस्तर के जंगलों से राष्ट्रपति भवन तक 'बड़ी दीदी' और गोडबोले दंपत्ति के मूक त्याग को मिलेगा देश का सर्वोच्च सम्मान

राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में होगा 'पीपल्स पद्म' का महासंगम
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी वनांचल के वास्तविक नायकों का सम्मान

शहर सत्ता/रायपुर। डॉ. बुधरी ताती का 'बड़ी दीदी' बनकर सुदूर गाँवों तक पहुँचना और गोडबोले दंपत्ति का आदिवासी समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए वर्षों तक किया गया निस्वार्थ कार्य आज की युवा पीढ़ी के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। कल जब राष्ट्रपति भवन की भव्य दीवारें इन महान विभूतियों के योगदान की गूंज से गुंजायमान होंगी, तब पूरा छत्तीसगढ़ और देश गर्व से मुस्कुराएगा। यह 'पीपल्स पद्म' इस सत्य का उद्घोष है कि भारत अपने उन सपूतों को कभी नहीं भूलता, जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की नींव को मजबूत करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं।

भारतीय गणराज्य की गौरवशाली परंपरा में कल (सोमवार) एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित भव्य नागरिक अलंकरण समारोह में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के उन अनमोल रत्नों को 'पद्म पुरस्कार' से अलंकृत करेंगी, जिन्होंने बिना किसी प्रचार-प्रसार की इच्छा के समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों के जीवन को बदलने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। हाल के वर्षों में देश ने पद्म पुरस्कारों के स्वरूप को बदलते और इन्हें वास्तव में 'पीपल्स पद्म' (जनता का पद्म) बनते देखा है। पहले जहाँ ये सम्मान महानगरों की चकाचौंध, रसूखदारों और सत्ता के गलियारों तक सीमित माने जाते थे, वहीं अब ये पुरस्कार सुदूर जंगलों, दुर्गम पहाड़ों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और जनजातीय बस्तियों के उन साधकों तक पहुँच रहे हैं, जिन्होंने कभी किसी सम्मान की कामना ही नहीं की।

इसी कड़ी में कल का दिन विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के जनजातीय समाज के लिए गौरव का अवसर बनने जा रहा है। बस्तर संभाग के सुदूर, दुर्गम और नक्सल प्रभावित वनांचलों में स्वास्थ्य सेवा, कुपोषण के खिलाफ संघर्ष, बालिका शिक्षा, नशामुक्ति और महिला सशक्तीकरण की अलख जगाने वाले छत्तीसगढ़ के तीन महान समाजसेवियों—डॉ. बुधरी ताती ('बड़ी दीदी') तथा प्रख्यात समाजसेवी दंपत्ति डॉ. रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले—को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान 'पद्म श्री' से सम्मानित किया जाएगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्यों इन विभूतियों का सम्मान पूरे राष्ट्र और मानवता के लिए गौरव का विषय है।

डॉ. बुधरी ताती ('बड़ी दीदी')

500 गाँवों तक पैदल पहुँचकर सामाजिक परिवर्तन की अलख जगाने वाली महानायिका

छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर स्थित दंतेवाड़ा जिले के हीरानार गाँव की रहने वाली डॉ. बुधरी ताती को बस्तर अंचल का जनजातीय समाज अत्यंत सम्मान और स्नेह के साथ 'बड़ी दीदी' कहकर पुकारता है। पिछले चार दशकों से अधिक समय से वे सुदूर वनांचलों में वनवासी कल्याण, बालिका शिक्षा और महिला सशक्तीकरण के लिए अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। इसी मूक साधना और समाजसेवा के लिए उन्हें 'पद्म श्री' से सम्मानित किया जा रहा है।

जब रास्ते नहीं थे, तब बनीं सहारा

डॉ. बुधरी ताती की सेवा यात्रा वर्ष 1984 में शुरू हुई थी, जब बस्तर के घने जंगलों में न सड़कें थीं, न मोबाइल नेटवर्क और न ही बुनियादी सुविधाएँ। उस दौर में आदिवासी समाज के बीच जाकर उनका विश्वास जीतना किसी चुनौती से कम नहीं था। 'बड़ी दीदी' ने अबूझमाड़ और दंतेवाड़ा के नक्सल प्रभावित घने जंगलों के बीच सैकड़ों गाँवों की पैदल यात्राएँ कीं। उस समय वनवासी परिवार पूरी तरह वनोपज और दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर थे, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा उपेक्षित रह जाती थी। बुधरी ताती ने माता-पिता को धैर्यपूर्वक समझाया कि शिक्षा ही उनके बच्चों के भविष्य को बदल सकती है और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ सकती है।

महिला सशक्तीकरण की नई इबारत

'बड़ी दीदी' ने केवल बच्चों को स्कूल भेजने तक अपना कार्य सीमित नहीं रखा, बल्कि आदिवासी महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सिलाई-कढ़ाई एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए। उनके प्रयासों से अनेक आदिवासी महिलाएँ आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ी हुईं। उनकी प्रेरणा से कई आदिवासी बेटियाँ आज विभिन्न अस्पतालों में नर्स के रूप में कार्यरत हैं।

कुपोषण और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान

मारिया और मुरिया जनजातीय समुदायों के बीच कार्य करते हुए उन्होंने देखा कि जागरूकता के अभाव में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अत्यधिक थी। डॉ. बुधरी ताती ने पारंपरिक जनजातीय ज्ञान और आधुनिक स्वास्थ्य पद्धतियों के समन्वय से स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने का कार्य किया। इसके साथ ही उन्होंने शराबखोरी, घरेलू हिंसा और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी व्यापक अभियान चलाया। सीमित संसाधनों से शुरू हुआ उनका यह प्रयास आज बस्तर के सामाजिक परिवर्तन की मिसाल बन चुका है।

डॉ. रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले

जब समर्पण और मानवता की बात होती है, तब 'युगल श्रेणी' में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों का महत्व और बढ़ जाता है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचलों में चिकित्सा एवं सामाजिक सेवा की नई परिभाषा गढ़ने वाले डॉ. रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले को संयुक्त रूप से 'पद्म श्री' से सम्मानित किया जा रहा है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा का कठिन सफर

बस्तर संभाग दशकों से नक्सली हिंसा और भौगोलिक दुर्गमता की चुनौतियों से जूझता रहा है। ऐसे समय में, जब मुख्यधारा के डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता इन क्षेत्रों में जाने से कतराते थे, तब गोडबोले दंपत्ति ने अबूझमाड़ और आसपास के दुर्गम इलाकों को अपनी कर्मभूमि बनाया। उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष आदिवासी क्षेत्रों की सेवा में समर्पित कर दिए। उनका उद्देश्य था कि स्वास्थ्य सेवाएँ उन लोगों तक पहुँचें, जिनकी आधुनिक चिकित्सा तक पहुँच लगभग न के बराबर थी।

कुपोषण और शिशु स्वास्थ्य के खिलाफ संघर्ष

आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, जागरूकता की कमी और अंधविश्वास के कारण बच्चों में कुपोषण गंभीर समस्या बना हुआ था। गोडबोले दंपत्ति ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए—

1. कुपोषित बच्चों की पहचान कर स्थानीय स्तर पर पौष्टिक आहार योजनाओं को बढ़ावा दिया।
2. दुर्गम गाँवों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए।
3. आदिवासियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर उन्हें आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया।

मानवीय सेवा का व्यापक स्वरूप

गोडबोले दंपत्ति का कार्य केवल दवाइयाँ बाँटने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आदिवासी समाज के समग्र कल्याण, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया। उन्होंने युवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य तकनीकों का प्रशिक्षण देकर ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया। उनकी निस्वार्थ सेवा के कारण बस्तर के अनेक आदिवासी उन्हें आज भी अत्यंत सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं।

'पीपल्स पद्म': पुरस्कार व्यवस्था में बदलाव की नई तस्वीर

नई दिल्ली में आयोजित होने वाला यह समारोह इस बात का प्रमाण है कि पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया अब अधिक लोकतांत्रिक और जन-केंद्रित हुई है। अब देश का कोई भी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से किसी गुमनाम नायक का नामांकन कर सकता है। चयन प्रक्रिया में प्रसिद्धि या राजनीतिक प्रभाव के बजाय जमीनी कार्य और सामाजिक प्रभाव को प्राथमिकता दी जा रही है। महानगरों से आगे बढ़कर अब बस्तर, अबूझमाड़ और दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को भी राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। इस वर्ष घोषित कुल 131 पद्म पुरस्कारों में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं, जो भारत की विविध प्रतिभाओं और सेवाभावी व्यक्तित्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कल जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं डॉ. बुधरी ताती और गोडबोले दंपत्ति को पद्म श्री प्रदान करेंगी, तब वह केवल एक पुरस्कार वितरण समारोह नहीं होगा, बल्कि उसका गहरा सामाजिक और प्रतीकात्मक महत्व भी होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं जनजातीय पृष्ठभूमि से आती हैं और उन्होंने जीवन में संघर्ष तथा अभावों को निकट से देखा है। ऐसे में उनके हाथों से वनांचलों में कार्य करने वाले इन समाजसेवियों को सम्मान मिलना विशेष रूप से प्रेरणादायक माना जा रहा है। यह सम्मान इस बात का भी संदेश है कि देश अब बस्तर जैसे क्षेत्रों को केवल संघर्ष और हिंसा के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक परिवर्तन की भूमि के रूप में भी पहचान रहा है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27